04 - पर्यावरण कानूनों की सर्वोच्चता का निर्णायक संदेश

05 - मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल

A Daily News Magazine

भोपाल

बुधवार, 12 अगस्त, 2026

06 - कॉलेज में लौटती लोकतंत्र की रौनक

07 - अम्मा बोली थी-कार गुजर गई, हम भी निकल जाएंगे...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 331, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

पाक-तुर्क-सऊदी गुटबंदी से भारत की सैन्य रणनीति प्रभावित होगी

ब्रिगेडियर अनिल रमन (रि)

पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब ने हाल में जिस मक्का समझौते की घोषणा की है उसका भारत के रक्षा योजनाकारों को काफी सावधानी से विश्लेषण करने की जरूरत है। जब इसकी तैयारी चल रही थी, तब भारत इसे भू-राजनीति वाले पहलू के चश्मे से देख रहा था और इस सवाल पर विचार कर रहा था कि कहीं यह मध्य-पूर्व में बन रहे एक नए समीकरण का संकेत तो नहीं है या क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक कूटनीतिक संदेश तो नहीं है। विश्लेषण में मुख्यतः ज़ोर इसके क्षेत्रीय और रणनीतिक प्रभावों पर रहा है।

वैसे, भारतीय सेना के लिए सवाल ऑपरेशन से जुड़ा है। सैन्य अभियान दो प्रमुख तत्वों से तय होते हैं– एक तो रणक्षेत्र से, जहां युद्ध होना है; दूसरे, उन राजनीतिक स्थितियों से, जिनके तहत युद्ध होना है। यह जो गुटबंदी हुई है, वह इन दोनों तत्वों में बदलाव ला सकती है। यह लड़ाई के मैदान में पाकिस्तान की क्षमता बढ़ा सकती है और उस राजनीतिक दबाव को बढ़ा सकती है जो लड़ाई को जल्दी खत्म करा सकता है। यह भारत को अपनी सैन्य सफलताओं को रणनीतिक उपलब्धियों में बदलने के लिए कम समय दे सकता है। छोटी लड़ाई भारतीय रणनीति के लिए ज्यादा प्रतिकूल होगी। भारत विश्वसनीय लक्ष्यों के लिए लड़ता है जिसके लिए चरणबद्ध ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है–दुश्मन को कमजोर करने, उसका शोषण करने, खुद को मजबूत करने, और इतना बड़ा नतीजा हासिल करने के ऑपरेशन, जो पाकिस्तान को अपना हिसाब-किताब बदलने को मजबूर कर दे। हर चरण अपना समय लेता है। पाकिस्तान युद्धविराम की घोषणा तक ही टिके रहने की लड़ाई लड़ता है। राजनीतिक समयसीमा के लिहाज से कम होता एक-एक दिन भारत को पाकिस्तान के मुक़ाबले महंगा पड़ता है।

सऊदी अरब के अच्छे-खासे हित दोनों के साथ जुड़े हैं। ऊर्जा, निवेश, और आर्थिक क्षेत्रों में भारत के साथ उसके गहरे संबंध हैं। और पाकिस्तान के साथ रक्षा, वित्त और रणनीतिक मामलों में उसके संबंधों में विस्तार हो रहा है। सऊदी अरब का हित इसी में है कि क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा बाज़ारों, और 'विजन 2030' के तहत उसकी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को खतरा पहुंचाने वाली कोई लंबी लड़ाई न हो। इस गुटबंदी से फर्क यह पड़ा है कि सऊदी अरब की स्थिति बदल रही है। यह मुल्क एक उदार तीसरे पक्ष वाली मध्यस्थ की भूमिका से पाकिस्तान के साथ संधि करके उसके सहयोगी की भूमिका में आ गया है। और पाकिस्तान को भी सऊदी अरब से संधि के तहत समर्थन हासिल करने का जायज अधिकार होगा। भारतीय कमांडरों के लिए सामरिक सफलता को ऑपरेशन संबंधी उपलब्धि में बदलने की गुंजाइश छोटी हो जाएगी। यह गुटबंदी लड़ाई के मैदान का स्वरूप भी बदल सकती है। यह पाकिस्तान की सेना के आधुनिकीकरण में चीन की भूमिका को खत्म करने की जगह उसे केंद्रीय भूमिका प्रदान कर रही है। पाकिस्तान चीनी लड़ाकू विमानों, लंबी दूरी वाला एअर डिफेंस, सटीक मार करने वाले हथियारों, नौसैनिक अड्डों, और उपग्रह से निर्देशित जहाजरानी का इस्तेमाल करता है। जे-35 समेत फ़िफ्थ जेनरेशन वाले लड़ाकू विमानों को शामिल किए जाने के साथ पाक का चीन से सहयोग और गहरा होगा और चीन को इस उपमहादेश में सैन्य संतुलन को प्रभावित करने का एक और कुंजी थमाएगा। तुर्किये अलग तरह की क्षमताएं हासिल करने में योगदान देगा। इसके अलावा, तुर्क और पाकिस्तानी सेना, खासकर वायुसेनाएं एक नियमित संस्थागत तरीके से साथ-साथ ट्रेनिंग लेती हैं।

जो कुछ हो रहा है उसमें ज्यादा योगदान चीन-पाकिस्तान संबंधों का है और यह सऊदी अरब के बिना भी चलता रहेगा। यह सब युद्ध के दौरान चीन के साथ-साथ नाटो के एक सदस्य के जरिए सप्लाई का दूसरा चैनल तैयार करता है। हाल में हुई गुटबंदी का महत्व इस बात में है कि यह युद्ध के अलग-अलग प्लेटफॉर्म को निशाना बनाने की जगह पूरी संरचना को निशाना बनाती है। चीन उपग्रहों और हवाई सेंसरों के जरिए रणनीतिक ISR उपलब्ध कराता है। तुर्किये इसमें ऑपरेशन और सामरिक स्तरों पर ड्रोन 'आइएसआर' और युद्धक्षेत्र की निगरानी की व्यवस्था जोड़ता है। ये दोनों मिलकर युद्धक्षेत्र की ज्यादा मजबूत तस्वीर तैयार कर सकते हैं। इसके कारण भारत को सेना की तैनाती, रिजर्व सेना के मूवमेंट, साजोसामान, और हेडक्वार्टरों को गुप्त रखने में मुश्किल हो सकती है।

यह संरचना पाकिस्तान की नई आर्मी रॉकेट फोर्स के लिए 'फोर्स मल्टीप्लायर' का काम करेगी। लंबी दूरी तक सटीक मार करने वाले हथियारों को नेटवर्क का सहारा चाहिए। चीन के रणनीतिक 'आइएसआर' के साथ तुर्क की सामरिक निगरानी सिस्टम के बूते पाकिस्तान दूर तक अपने टार्गेट की खोज और पीछा करने तथा निशाना बनाने की क्षमता बढ़ा सकता है। ऐसे में भारतीय सेना के हेडक्वार्टर्स, साजोसामान के अड्डे, पुल, रिजर्व सेना के अड्डे, हवाई अड्डे, गोला-बारूद के भंडार, और डिफेंस मैनुफैक्चरर तथा सैन्य उद्योग निशाने पर आ जाएंगे। भारत के पास काफी दूर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं लेकिन उसे ऐसी आर्मी रॉकेट फोर्स तैयार करनी है जिसके साथ एक ओपरेशनल कमांड के तहत थिएटर के काम आने वाली 'ISR', निशाना बनाने वाली व्यवस्था और लंबी दूरी तक फायर करने वाली क्षमता जुड़ी हो।

ड्रोन, इलेक्ट्रोनिक युद्ध, प्रिसीजन वेपन के साथ जमीनी कार्रवाइयों का तालमेल बैठाने के जो तुर्क प्रयोग हैं, वे पाकिस्तानी सेना के साथ तालमेल से काम करने की पाकिस्तानी वायुसेना की लंबी परंपरा को मजबूती दे सकते हैं। भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों के अधिकृत से कम संख्या में स्क्वाड्रन ऑपरेट करती है। पाकिस्तान में जो सुधार हो रहे हैं उनसे भारत के लिए ऑपरेशन से संबंधित कोई नई चुनौती नहीं पैदा हुई है। वे मौजूदा कमजोरियों को गंभीर बनाते हैं।

एकीकृत सैन्य टुकड़ियों की ओर कदम बढ़ाने के बावजूद भारत में ऑपरेशनों की जो अवधारणा है वह बड़े हेडक्वार्टर्स, केंद्रीकृत साज-ओ-सामान अड्डों, आर्मर्ड फॉरमेशनों पर आधारित है जिन्हें बीते दौर के लिए डिजाइन किया गया था। मजबूत 'ISR', ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और प्रिसीजन फायर यह सवाल खड़ा करते हैं कि वे ढांचे कितनी देर तक टिक पाएंगे। चुनौतियां केवल खरीद के मामले में नहीं हैं। सवाल ऑपरेशन के डिजाइन के भी हैं, जो अगला युद्ध लड़ने की भारतीय सेना की योजना को स्वरूप प्रदान करेंगे।

पाकिस्तान ने साझीदारी आधारित मॉडल को अपनाया है। भारत की स्थितियां भिन्न हैं। एक बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ अच्छी-ख़ासी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक क्षमता के बावजूद आत्मनिर्भरता उसका दीर्घकालिक लक्ष्य बना हुआ है। सवाल क्रम निर्धारण का है। पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब की गुटबंदी को केवल कूटनीतिक घटना न मानें, उसका आकलन ऑपरेशन के नजरिए से भी करें। यह युद्धक्षेत्र में पाकिस्तान को मजबूत बनाने के अलावा ऐसे राजनीतिक हालात पैदा कर सकती है कि भारत को ताकत के इस्तेमाल के लिए कम समय रहे। दोनों बातें एक साथ लागू होती हैं।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने करवाया झारखंड बंद

● स्कूल, दफ्तर खुले, कई जगह बाजार बंद रहे ● विधानसभा घेराव के दौरान ABVP कार्यकर्ताओं-पुलिस में झड़प

रांची (एजेंसी)। झारखंड के रांची में सोमवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने मंगलवार को राज्यव्यापी बंद बुलाया। रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई जगह सड़कें जाम कीं। कुछ जिलों में कार्यकर्ता जबरन दुकानें बंद कराते भी नजर आए। कई शहरों में पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि, कई प्राइवेट स्कूल खुले हुए थे।

इधर, झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। कार्यकर्ता पुरानी विधानसभा के पास जुटे थे, जहां उन्हें हिरासत में लेने के लिए पुलिस पहुंची। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए, जबकि कुछ पुलिस वैन के आगे बैठ गए।

हेमंत सरकार का बड़ा फैसला

14वीं जेपीएससी पीटी समेत 2023-25 की कई परीक्षाएं होंगी रद्द- झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के बीच

हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने 14वीं जेपीएससी पीटी समेत कई परीक्षाएं रद्द करने और अन्य परीक्षाओं की जांच कराने का ऐलान किया है।

सीएम हेमंत बोले- विपक्ष युवाओं को भटका रहा है- झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार छात्र आंदोलन का मुद्दा उठा रहा है।

संसद में गतिरोध रहा कायम हंगामे के चलते हुई स्थगित

● संसद परिसर में एनडीए-कांग्रेस सांसद आमने-सामने आए ● भाजपा सांसद ने पूछा- राहुल झारखंड क्यों नहीं गए, प्रियंका का जवाब- वे छात्रों से मिल चुके

नईदिल्ली (एजेंसी)। संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने मंगलवार को एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने भी आ गए।

प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने पर भाजपा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। भाजपा सांसद मुकेश दलाल ने पूछा कि राहुल झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं। प्रियंका मुस्कुराती हुई उनके पास गईं और कहा- राहुल झारखंड गए हैं और छात्रों से मिल चुके हैं।

लोकसभा और राज्यसभा में भी हंगामा

हुआ। लोकसभा की कार्यवाही पहले 11 बजे तक स्थगित की गई। दोपहर 2 बजे सदन दोबारा शुरू हुई थी, लेकिन करीब आधे घंटे बाद ही हंगामे के चलते कार्यवाही बुधवार तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है।

लोकसभा में केरल-नाम परिवर्तन विधेयक, 2026 पारित

संसद के मानसून सत्र के 17वें दिन भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच

गतिरोध बना रहा। संसद में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। हंगामे के बीच लोकसभा में केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित हुआ। हंगामे के बीच लोकसभा में

सुप्रभात

हम बहुत कुछ यूँ
हीं संभाल लेते हैं
वो कुछ बोलें,
तो हसँकर टाल देते हैं
इन आँखों से ही
बातें करना है बेहतर
ये लफ्ज तो,मसअला
ही बिगाड़ देते हैं
मेरी जबां में शायद
थोड़ी सी तल्खी है
लाओ इसमे थोड़ी
मोहब्बत डाल देते हैं
मैंने लबों को सी रखा है
बस इसी खातिर
कुछ गलत होने पे ये
सवाल दाग देते हैं
कानून बिक चुका है
सफेदपोशों के हाथों
किसी का इल्जाम किसी के
सर डाल देते है
जब माँ नौ माह रख
सकती है उन्हें पेट में
फिर क्यूँ ही बच्चे उसे
घर से निकाल देते हैं
दौरे- दुनियाँ और लोगों की
रवायत देखो
माँ बाप को घर से
निकाल,कुत्ते पाल लेते हैं
इस ज़माने से तुम संभल
कर रहना यारों
मोहब्बतों में भी लोग
नफरत निकाल लेते हैं !!

– भास्कर उपाध्याय

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये कई निर्णय

भोपाल-विदिशा फोरलेन को दी मंजूरी

1757.55 करोड़ रुपए होंगे खर्च ; 44.83 किमी मार्ग होगा 4-लेन, तीन बायपास बनेंगे

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक संपन्न हुई। मंत्रि-परिषद ने भोपाल को मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस पहल करते हुए भोपाल-विदिशा मार्ग के 2-लेन से 4-लेन उन्नयन एवं निर्माण के लिए 1757.57 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इस मार्ग के निर्माण से तेजी से औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और अधोसंरसचना का भी व्यवस्थित विकास हो पायेगा। सांची स्तूप और कर्क रेखा जैसे प्रमुख स्थलों से गुजरने वाला यह मार्ग प्रादेशिक कनेक्टिविटी को नई मजबूती देगा। मंत्रि-परिषद ने भोपाल बासपास को 6-लेन बनाने के दृष्टिगत भोपाल बायपास- टोल टैक्स शुल्क संग्रहण की अनुमति 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रि-परिषद ने स्थानीय मजदूरों और क्षेत्र के रहवासियों को लाभांश वितरण के लिए वन विभाग द्वारा संचालित संयुक्त वन प्रबंध समितियों को लाभांश का प्रदाय योजना के तहत वर्ष 2030-31 तक निरंतर रखे जाने की 918 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। मंत्रि-परिषद ने किसान वर्ष में किसानों को बड़ी सौगात देते हुए भारत सरकार के अंतर्गत गठित उपक्रम नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए सीहोर जिले की इछावर तहसील के गांव भाउखेड़ी में 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया है।

वनोपज समितियों के जरिए मिलेगा लाभांश

वनोपज से जुड़े काम में लगे लोगों को मजदूरी देने के साथ ही लाभांश का वितरण स्थानीय स्तर पर समितियों के माध्यम से किया जाएगा। इसमें काम करने वाले स्थानीय लोगों को लाभांश का लाभ देने पर चर्चा हुई।

होम स्टे से जुड़े लोगों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

प्रदेश में होम स्टे इकोसिस्टम से जुड़े लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण पर्यटन विभाग के माध्यम से कराया जाएगा, ताकि होम स्टे से जुड़े लोगों की सेवाओं और रोजगार के अवसरों को बेहतर किया जा सके।

तीन बायपास भी बनेंगे

परियोजना में कुल 8.25 किलोमीटर लंबाई के तीन बायपास बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इससे आबादी वाले क्षेत्रों में वाहनों का दबाव कम होगा और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी घटेगी। परियोजना की लागत पहले 1467.42 करोड़ रुपए स्वीकृत हुई थी। बाद में यह बढ़कर 1617.04 करोड़ रुपए हुई। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि अधिग्रहण के लिए करीब 140 करोड़ रुपए अतिरिक्त लगने के बाद कुल लागत 1757.55 करोड़ रुपए हो गई।

सांची, उदयगिरि समेत पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी होगी बेहतर

भोपाल-विदिशा मार्ग केवल यातायात के लिहाज से ही नहीं, बल्कि धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके आसपास सांची स्तूप, संग्रहालय, अशोक स्तंभ और उदयगिरि की गुफाएं सहित कई पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक स्थल हैं। मार्ग करीब 24.550 किलोमीटर पर कर्क रेखा से भी गुजरता है, जिससे इसका भौगोलिक महत्व बढ़ जाता है। फोरलेन बनने से भोपाल से विदिशा और सांची तक यात्रा अधिक सुगम होगी। इससे पर्यटन, होटल, परिवहन, गाइड सेवा, हस्तशिल्प और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रायसेन, सांची और विदिशा को बायपास करते हुए बनाए जा रहे नए फोरलेन मार्ग से जुड़कर यह परियोजना भोपाल, सागर, दमोह, छतरपुर और पन्ना सहित उत्तर-पूर्वी मध्यप्रदेश की कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगी।

आन-बान-शान के साथ मनाएं 15 अगस्त

पीएम मोदी ने देशवासियों से की 'हर घर तिरंगा' अभियान में शामिल होने की अपील

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस गर्व और सम्मान के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लें। उन्होंने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और स्वतंत्रता दिवस के जश्न में उत्साह के साथ शामिल होने का आह्वान किया।

पीएम मोदी ने कहा, हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। उन्होंने लोगों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने और स्वतंत्रता दिवस के जश्न में उत्साह के साथ शामिल होने का आह्वान किया। मंगलवार को पीएम मोदी ने कहा, आइए हम सभी लोग 15 अगस्त आन-बान-शान के साथ मनाएं।

स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें और विकसित भारत के संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।

● लाल किले पर पहली बार गाया जाएगा वंदे मातरम्- केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 15 अगस्त को ऐतिहासिक लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गाया जाएगा और इस कार्यक्रम की थीम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा शक्ति का योगदान होगी।भारत 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 12 अगस्त 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

अमेरिका के चांद वाले अड्डे पर इसरो भी जमाएगा आसन

भारत की बड़ी 'उड़ान'

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका ने अब भारत की वैज्ञानिक सोच और प्रगति का लोहा मान लिया है। वह नासा और इसरो के निसार मिशन की कामयाबी को देखते हुए अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहा है। साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को अपने 'मून बेस प्रोग्राम' में शामिल होने का न्योता भी दिया। यह प्रस्ताव 'आर्टेमिस समझौते' के तहत दोनों देशों के बीच सहयोग पर आधारित है, जो चंद्रमा की खोज में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा (फ्रेमवर्क) प्रदान करता है।

- **भारत-अमेरिका अंतरिक्ष के क्षेत्र में साथ भरेंगे उड़ान-** भारत और अमेरिका अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान, वैज्ञानिक अनुसंधान, चंद्रमा की खोज और कमर्शियल अंतरिक्ष गतिविधियों जैसे विषयों पर बातचीत शामिल है। ये बातचीत 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय में हुई 'भारत-अमेरिका सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप' की नौवीं बैठक के दौरान हुई। इस बैठक में इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (नासा) और अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी शामिल हुए, ताकि मौजूदा सहयोग की समीक्षा की जा सके और साझेदारी के नए क्षेत्रों पर चर्चा की जा सके।
- **अमेरिका के मून बेस प्रोग्राम में इसरो को न्योता-** भारत में अमेरिका दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर इसरो और नासा के बीच हुए सहयोग के बारे में जानकारी दी। एक अहम घटनाक्रम यह रहा कि नासा ने इसरो को अपने 'मून बेस प्रोग्राम' में शामिल होने का न्योता दिया।
- **आर्टेमिस फ्रेमवर्क के तहत भारत-अमेरिका में सहमति-** भारत और अमेरिका 'आर्टेमिस फ्रेमवर्क' के तहत ओपन साइंटिफिक डेटा साझा करने पर बातचीत जारी रखने पर भी सहमत हुए। दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष विज्ञान और मानव अंतरिक्ष उड़ान तकनीकों में भविष्य की साझेदारी विकसित करने के तरीकों पर चर्चा की।

कमिश्नर ने बढ़ाई शिक्षकों की फजीहत, फिर बदला टाइम

अब 10 बजे के पहले लगाना होगा ई अटेंडेंस, 10.30 बजे तक अटेंडेंस लगाने वाले बताएंगे कारण

भोपाल (नप्र)। ई-अटेंडेंस सिस्टम लागू कर प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक्टिव लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने शिक्षकों की फजीहत बढ़ा दी है।

अब शिक्षकों को ताजा निर्देश जारी कर कहा गया है कि उन्हें दस बजे के पहले विद्यालय में पहुंचकर ई अटेंडेंस लगाना होगी। इसके बाद अगर साढ़े दस बजे तक ई अटेंडेंस लगाते हैं तो देरी का कारण बताना होगा। इस अवधि के बाद ई अटेंडेंस को मान्य नहीं किया जाएगा। लोक शिक्षण आयुक्त ने यह निर्देश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग से ली गई बैठक में आयुक्त सिंह ने कहा है कि ई-अटेंडेंस को लेकर किसी तरह की लापरवाही से वेतन कट सकता है। इसलिए शिक्षकों, लोकसेवकों की जिम्मेदारी है कि वे समय पर विद्यालय में उपस्थित हों और पठन पाठन के कार्य में शामिल हों। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर दिए ताजा निर्देश में आयुक्त ने कहा है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से पूर्व संस्था में उपस्थित होना है। यहां बता दें लोक शिक्षण आयुक्त के निर्देश पर सोमवार को विभाग के कर्मचारियों, अफसरों को यह सूचना दी गई थी कि अब सुबह 10.30 बजे तक ई अटेंडेंस लगाना होगी, हालांकि सोमवार को सुबह 11 बजे तक शिक्षकों, कर्मचारियों की अटेंडेंस लगती रही थी।

संक्षिप्त समाचार

10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों को मंजूरी

वित्त मंत्री निर्मला बोलीं- ट्रायल में दोनों के 100-100 करोड़ नोट छपेंगे, ये 30 साल तक चलेंगे

नईदिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। दोनों के 100-100 करोड़ पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोट जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी। आरबीआई ने 10 और 20 रुपए के 100-100 करोड़ पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल का प्रस्ताव दिया था। ट्रायल सफल होने के बाद इन दोनों के पॉलीमर नोट नियमित रूप से जारी किए जाएंगे।

अब 'वंदे मातरम्' का अपमान होगा अपराध

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून हुआ लागू

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का अपमान करना अब अपराध माना जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से 'वंदे मातरम् बिल' को मंजूरी मिलने के बाद आज मंगलवार, 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह कानून बन गया है। इस कानून के लागू होने से राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को जानबूझकर गाने से रोकना या उसमें बाधा डालना अपराध माना जाएगा। इस बिल से इसे वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो अभी राष्ट्रीय गान को मिलती है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026 अब कानून बन गया है।

वाराणसी घूमने आए महाराष्ट्र के कारोबारी की होटल में मौत

दाह संस्कार कर लौटे पत्नी-बेटे ने भी दी जान

वाराणसी (एजेंसी)। वाराणसी में घूमने आए महाराष्ट्र के कारोबारी की मौत के बाद उसकी पत्नी और बेटे ने सुसाइड कर लिया। यह परिवार महाराष्ट्र से 7 अगस्त को बनारस पहुंचा था। यहां तीन दिनों तक उन्होंने गंगा स्नान किया और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर काशी का भ्रमण किया। इस दौरान 9 अगस्त की देर रात होटल में अचानक से कारोबारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया।

फसल बीमा योजना

अब किसानों को क्लेम के वक्त नहीं होगी परेशानी

- **राजस्थान सरकार ने खरीफ के लिए नए दिशा-निर्देश जारी**

जयपुर (एजेंसी)। कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पॉलिसियों को जारी करने से पहले वेरिफिकेशन सुनिश्चित करना होगा। राजस्थान में पीएम फसल बीमा योजना के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये निर्देश खरीफ 2026 से लागू होंगे।

होगा पॉलिसी का वेरिफिकेशन

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि जिन किसानों ने ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन नहीं लिया है, उनकी पॉलिसी का वेरिफिकेशन निर्धारित निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिसूचित बीमा कंपनी की होगी। उन्होंने बताया कि ऋणी किसानों की पॉलिसी सृजित करते समय किसानों की सहमति नहीं लेने तथा वास्तविक बोई गई फसल का बीमित फसल से मिलान न होने के कारण क्लेम भुगतान के समय विवाद उत्पन्न होते हैं। इसका समाधान पॉलिसी जारी करने के समय ही फसल की वेरिफिकेशन किया जाना जरूरी है।

वीरेश कुमार त्यागी की शब्द-साधना को राजेंद्र 'राजन' स्मृति गौरव सम्मान

उनकी पंक्तियों में गाँव की चौपाल और घर-आंगन की आत्मीयता

सहारनपुर। पेशे से किसान और मन से कवि वीरेश कुमार त्यागी को 'गीतकार राजेन्द्र 'राजन' स्मृति गौरव सम्मान' से नवाजा गया। यह सम्मान केवल एक रचनाकार का अभिनंदन नहीं, बल्कि उस लोक-संवेदना का सम्मान है, जो खेत से उठकर कविता में मनुष्य की आवाज बनती है।

सहारनपुर जनपद के देवबंद क्षेत्र के कुरडी गांव की मिट्टी में पले-बढ़े वीरेश कुमार त्यागी का रचना-संसार किसी साहित्यिक प्रयोगशाला में नहीं, जीवन की खुली पाठशाला में तैयार हुआ है। उन्होंने मौसम को कैलेंडर से नहीं, आकाश और खेत की आँखों से पढ़ा है। बारिश उनके लिए सिर्फ पानी नहीं, उम्मीद है; सूखा केवल खेत की पीड़ा नहीं, मनुष्य की संवेदना के सूख जाने का रूपक भी है। हरियाली उनके यहाँ फसल के साथ-साथ जीवन के भीतर बची आस्था का रंग है। उनकी कविता की सबसे बड़ी खूबी उसकी सहजता है। वह शब्दों का श्रृंगार करके पाठक को चमत्कृत करने के बजाय जीवन की सच्चाई उसके सामने रख देती है। उनकी पंक्तियों में गाँव की चौपाल है, घर-आँगन की आत्मीयता है, रिश्तों की गरमाहट है और बदलते समय के बीच मनुष्य के अकेले पड़ते जाने की चिंता भी। वे गाँव को केवल स्मृति के रूप में नहीं देखते; उनके लिए गाँव हमारी सामाजिक चेतना की वह जड़ है, जिससे कटकर विकास भी अधूरा हो जाता है। राजेन्द्र 'राजन' की स्मृति में मिला यह सम्मान इसलिए भी अर्थवान है कि राजन स्वयं गीत की उस परंपरा के प्रतिनिधि थे, जिसमें लोकजीवन, मनुष्य और संवेदना एक-दूसरे से अलग नहीं होते। वीरेश कुमार त्यागी की रचनात्मक यात्रा भी इसी जीवित परंपरा को आगे बढ़ाती दिखाई देती है। आज जब साहित्य और जीवन के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, वीरेश कुमार त्यागी जैसे कवि याद दिलाते हैं कि कविता किताबों से पहले जीवन में जन्म लेती है। वह खेत में अंकुर की तरह फूटती है, पसीने में आकार लेती है और शब्द बनकर मनुष्य तक पहुँचती है।

भारत की चीन को दो टूक

अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा, इसे कोई बदल नहीं सकता

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश और अरुणाचल प्रदेश से जुड़े दो अहम मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारतीय दूत दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान से मुलाकात की। भारत ने उन्हें द्विपक्षीय यात्रा के साथ-साथ दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स आउटरीच सत्र के लिए भी आमंत्रित किया है।

दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत-चीन सीमा संबंधी मामलों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीमा की स्थिति का असर दोनों देशों के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ता है।

चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश को लेकर आई प्रतिक्रिया पर पूछे गए सवाल के जवाब में रणधीर जायसवाल ने भारत की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक ऐसी वास्तविकता है जो स्वयं स्पष्ट है और इस निर्विवाद सच्चाई को कुछ भी नहीं बदल सकता।

पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसूनी बारिश का कहर

- **मप्र-राजस्थान-उप्र समेत 6 राज्यों में 48 घंटे से लगातार बारिश**
- **हिमाचल में चलती कार पर पत्थर गिरे, 259 सड़कें बंद, चमोली में बादल फटा, ब्रिज, बीआरओ कर्मचारी और वाहन बहे**

नई दिल्ली/ जयपुर/ देहरादून/ भोपाल/ लखनऊ (एजेंसी)। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। उप्र में भी लगातार बारिश जारी थी गंगा-यमुना उफान पर थी।

भोपाल में दो दिन से बारिश जारी है। यहां 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। स्कूलों में दो दिन की छुट्टी कर दी गई। शहर में 1,000 से ज्यादा घरों के आसपास 5 फीट तक पानी भर गया।

राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 17 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में हाड़ौती क्षेत्र (कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़) में 12 इंच तक बारिश हुई।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एनएच-305 पर चलती गाड़ी पर मलबा और चट्टानें गिर गईं। हादसे में गाड़ी सवार दो लोग घायल हो गए, जबकि गाड़ी मलबे के नीचे दब गई।

गुजरात में महिसागर के सुवा गांव में बाढ़- गुजरात के महिसागर जिले में भारी बारिश के सुवा गांव में बाढ़ आ गई है।

सोनिया गांधी बोलीं

मनमोहन सिंह सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक थे

उनकी ईमानदारी का रिकॉर्ड भाजपा सरकार से अलग, इतिहास उन्हें सम्मान से याद करेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लीन चिट मिलने के कुछ दिन बाद कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया ने मंगलवार को मीडिया में प्रकाशित अपने आर्टिकल में मनमोहन सिंह और मोदी सरकार के कामकाज की तुलना की। सोनिया ने लिखा कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी और जवाबदेही का रिकॉर्ड मोदी सरकार के काम करने के तरीके से बिल्कुल उल्टा था।

आस्था का अनोखा अंदाज!

- **सुमित की साइकिल से 26 हजार किमी की यात्रा, 21 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग कवर**

खटीमा (उत्तराखंड) (एजेंसी)। हौसले बुलंद और मंजिल पाने का दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। खटीमा के युवा सुमित राजभर ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। सुमित राजभर ने साइकिल पर सवार होकर करीब 26 हजार किलोमीटर का सफर, 21 राज्यों का भ्रमण, 12 ज्योतिर्लिंग और चार धामों के दर्शन किये हैं।

एक साल बाद सुमित राजभर ने अपने गांव वापसी की है। खास बात ये रही कि घर लौटते वक्त सुमित हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल कांवड़ यात्रा करते हुए गांव पहुंचे। खटीमा पहुंचने पर लोगों ने फूल-मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। सुमित की ये यात्रा सिर्फ आस्था की कहानी नहीं, बल्कि नशामुक्त भारत और युवाओं

को दृढ़ संकल्प का संदेश देने की प्रेरणादायक मुहिम भी रही। सुमित ने करीब एक साल तक साइकिल से देश भ्रमण करते हुए 26 हजार किलोमीटर का सफर तय किया। 21 राज्यों में पहुंचकर 12 ज्योतिर्लिंगों व चार धामों के दर्शन किए. 25 अगस्त 2025 को शुरू हुई उनकी यात्रा 10 अगस्त 2026 की शाम अपने गांव लौटने के साथ पूरी हुई। खास बात यह रही कि घर वापसी के दौरान सुमित ने हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल कांवड़ यात्रा भी की।

नीट खत्म करने का प्रस्ताव तमिलनाडु विधानसभा में पास

नईदिल्ली (एजेंसी)। बार-बार पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की तैयारी तेज हो गई है। तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में नीट सिस्टम खत्म करने का प्रस्ताव पास करा लिया है।

- **सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा अपील का क्या हो रहा है, यह भी देखना जरूरी है**

प.बंगाल में एसआईआर डिलीशन

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से उन अपीलों की जानकारी मांगी, जिनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल ने किया है। ये ट्रिब्यूनल पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान लिस्ट से हटाए गए लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए बनाए गए थे। बेंच ने कहा कि अपील का क्या हो रहा है, यह भी देखना जरूरी है।

- **नेताजी की अस्थियां टोक्यो से भारत लाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस-** सुप्रीम कोर्ट ने टोक्यो के रेंकोजी मंदिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 'अस्थियां' वापस लाने का निर्देश देने संबंधी उनकी बेटी की याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। अदालत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी की अर्जी पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है।
- **डिजिटल नुकसान के खिलाफ निगरानी तंत्र के लिए पीआईएल को रिप्रेजेंटेशन के तौर पर मानें -** सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से गंभीर साइबर अपराधों - जैसे मारपीट की धमकी, बच्चों के स्कूल के ठिकानों जैसी निजी जानकारी उजागर करने और सहमति के बिना निजी सामग्री साझा करने - के खिलाफ सुधार के उपायों की मांग करने वाले एक अभ्यावेदन पर विचार करने को कहा।

वंदे मातरम् के जयघोष के साथ हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक

नईदिल्ली (एजेंसी)। संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक शुरू हो गई। बैठक की शुरुआत 'वंदे मातरम्' के जयघोष के साथ हुई। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के अन्य नेता बैठक में शामिल हुए।

भोपाल में घी के 27 में से 13 नमूने असुरक्षित

इंदौर में 8 असुरक्षित, कमिश्नर ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया

भोपाल (नप्र)। दूध, घी और दूध से बने उत्पादों में मिलावट न हो, इसलिए खाद्य एवं औषधि विभाग पूरे प्रदेश में अभियान चला रहा है। इस दौरान मिलावटखोरी के आंकड़े चौंका रहे हैं। विभाग के अनुसार, घी के कुल 27 सुरक्षित नमूनों में 13 भोपाल, 8 इंदौर के है। इन्हें लेकर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।

भोपाल में द्वारकेश, शगुन, गोवर्धन, दानेदार, भूमि, धोलपुर फ्रेश, भूमि प्रीमियम प्योर के नमूने असुरक्षित पाए गए। डिंडौरी के वास्तु और गोपी श्री, इंदौर के 8- श्री सुधा प्रीमियम, गुमार प्योर, शुद्ध घी, गाय का घी, वास्तु एगमार्क देशी घी, उज्जैन के 2- एसआईएमआई मिल्क देशी घी और दमोह-धार का एक-एक नमूना असुरक्षित पाया है। इसके बाद विभाग अब आगे की कार्रवाई कर रहा है।

कुल 2234 सैंपल लिए गए

20 जुलाई से 10 अगस्त के बीच कुल 2234 दूध या दुग्ध उत्पादों के सैंपल लिए गए। इनमें दूध के 849, मावा के 106, पनीर के 296, घी के 601 और अन्य उत्पादन के 382 नमूने शामिल हैं। कुल 44 हजार 407 किलो सामग्री की कीमत 2.73 करोड़ रुपए है। इस दौरान 8 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। 73 नमूने फेल हुए। एफएसएस एक्ट के तहत 38 प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए एक मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई।

समीक्षा में लापरवाही सामने आई

अभियान के तहत मंगलवार को आयुक्त/नियंत्रक खाद्य एवं सुरक्षा प्रशासन ने प्रदेशव्यापी अभियान की समीक्षा की। इस दौरान तीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता मुरैना, प्रीति राय सागर एवं राजेश राय पन्ना को सौंपे गए कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं, विभिन्न जिलों के 42 उप संचालक/अभिहित अधिकारियों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी सिविल सेवा आचरण नियम अंतर्गत कारण बताओ नोटिस/ स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

पेट्रोल में पानी मामले में आज होगी जांच

भोपाल के 80 फीट रोड और जहांगीराबाद स्थित दो पेट्रोल पंप में सोमवार को हंगामा हुआ था। यहां के पेट्रोल में पानी मिला हुआ पाया गया था। इस पर ग्राहकों ने हंगामा कर दिया था। खाद्य विभाग ने दोनों ही पंप सील कर दिए हैं और मंगलवार को कार्रवाई करने जाने वाली थी, लेकिन जांच नहीं हुई। फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया कि बुधवार को जांच करने के लिए टीम मौके पर भेजी जाएगी।

राहुल रोज झूठ बोलते हैं, इससे भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही

सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी को लताड़ा

भोपाल (नप्र)। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक में बीजेपी ने हमला बोला है। सीएम मोहन यादव ने भी भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी रोज झूठ बोलते हैं। उनके व्यवहार से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है।

राहुल गांधी देश से माफी मांगे

सीएम मोहन यादव ने कहा कि इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल अपने ही पार्टी के अन्य सदस्यों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी 15 दिनों से संसद की कार्यवाही को लगातार बाधित कर रहे हैं।

देश और सांसदों को भ्रमित कर रहे

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नित नए झूठे हथकंडे लगाकर देश को-सांसदों और समाज का भ्रमित कर रहे हैं। मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहूंगा कि यह गलत है। विपक्ष गृह मंत्री जवाब दें-गृह मंत्री जवाब दें, कहकर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है। विपक्ष एक बात पर टिक ही नहीं पा रहा। नीट की बात करते-करते गोली चलाने की बात पर पहुंच गए। जब गोली चली ही नहीं तो, उसकी बात कैसे होगी।

भारत की साख गिरा रही कांग्रेस

सीएम मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों की बात करते हैं, लेकिन झारखंड के मसले को लेकर यूपी पहुंच जाते हैं। इस तरह से कार्यवाही नहीं चलती। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सदन में बात करनी चाहिए। मोहन यादव ने कहा कि उनके निंदनीय व्यवहार से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। इसलिए भावी पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा कि हम अपने आचरण से मर्यादा बनाकर चलें। उन्होंने कहा कि रोज नया झूठ बोलने और चालाकियां करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जनता सब जानती है। उनकी हरकतों की वजह से कांग्रेस के दूसरे नेताओं का भी अपमान होता है। मुझे उम्मीद है कि वे अपने आचरण को भविष्य में सुधारेंगे।

राज्यपाल पटेल से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की सौजन्य भेंट

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल से मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल श्री पटेल का मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर अभिवादन किया। राज्यपाल पटेल को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के विकास, जनकल्याण और महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थे।

नर्सिंग छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना

रिजल्ट जारी करने समेत 7 मांगें, नर्सिंग काउंसिल भोपाल के सामने प्रदर्शन

भोपाल (नप्र)। नर्सिंग छात्रों के संगठन एनएसओ ने विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग काउंसिल भोपाल के सामने 8 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। संगठन की ओर से पोस्टर जारी कर कहा गया है कि जब तक छात्रों की मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। धरना रोजाना सुबह 11 बजे से किया जा रहा है।

संगठन ने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट घोषित करने और आगामी परीक्षाएं कराने की मांग प्रमुखता से उठाई है। इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के GNM, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों को स्कॉलरशिप देने की मांग की गई है।

सभी शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ

हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश में मनाया जा रहा है उत्साह और उल्लास के साथ : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल से भेंट के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक भवन के बाहर मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी क्षेत्रों में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भारत की ओर आशान्वित भाव से देखती है। राज्य सरकार, प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकसित भारत@2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर विकास परक और जनकल्याणकारी कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्यपाल श्री पटेल को अवगत कराया कि प्रदेश में उत्साह और उल्लास के साथ हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत गतिविधियां जारी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्यपाल श्री पटेल से चर्चा के दौरान उन्हें अवगत कराया की राज्य सरकार ने सभी शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया आरंभ की है। पिछले दिनों प्रदेश के सभी पात्र अधिकारी और कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है। यह पदोन्नति प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी, हमारे अधिकारी-कर्मचारी कई वर्षों से पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ होने की प्रतीक्षा में थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्यपाल श्री पटेल को आगामी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रदेश स्तर पर जारी व्यापक तैयारियों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि भेंट के दौरान प्रदेश में इंदौर-उज्जैन और भोपाल-सीहोर मेट्रोपोलिटन सिटी बनाए जाने, विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सहित कई विधेयकों को पारित करने, अलनीनो प्रभाव के कारण राज्य में अब तक 15 प्रतिशत कम बारिश की स्थिति और प्रदेश में जारी विकासपरक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई।

विस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की पीएम मोदी से सौजन्य भेंट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष तोमर की केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात हुई।

भोपाल की झीलों में देशभर के सेलर्स का 'महामुकाबला'

12 राज्यों के करीब 100 खिलाड़ी उतरे ; 16 अगस्त तक चलेगी चैंपियनशिप

भोपाल (नप्र)। भोपाल का बड़ा तालाब अब सिर्फ पर्यटन का केंद्र नहीं, बल्कि देश के नए वाटर स्पोर्ट्स चैंपियन तैयार करने की जमीन बन रहा है।

अपर लेक स्थित बोट क्लब में मंगलवार से राजा भोज मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप (रैंकिंग) 2026 शुरू हुई। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 11 से 16 अगस्त तक चलने वाली इस राष्ट्रीय रैंकिंग प्रतियोगिता में 12 राज्यों के करीब 100 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सेलर्स हिस्सा ले रहे हैं।

प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी राष्ट्रीय रैंकिंग तय होगी। यह रैंकिंग आगे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी। 6 दिन तक चलने वाले मुकाबलों में खिलाड़ियों की रफ्तार, संतुलन, तकनीकी कौशल और रणनीति की परीक्षा होगी।

12 ज्यूरी मेंबर्स संभाल रहे तकनीकी जिम्मेदारी- प्रतियोगिता को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आयोजित करने के लिए याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का तकनीकी मार्गदर्शन मिल रहा है। बायएआई के 12 ज्यूरी मेंबर्स और पदाधिकारी भोपाल पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता के संचालन, तकनीकी व्यवस्थाओं और निर्णयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारतीय खेल प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भी आयोजन से जुड़े हैं।

16 अगस्त को मुख्यमंत्री करेंगे समापन- राजा भोज मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का समापन और पुरस्कार वितरण समारोह 16 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में होगा। विभिन्न वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा।

भोपाल में 1000 करोड़ का अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर

मंत्री ने कहा कि भोपाल में करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर विकसित किया जा रहा है। इसके पहले चरण का लोकार्पण जल्द होगा। नवंबर में इसी परिसर में अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय एशियन रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी भी भोपाल करेगा।

बड़े तालाब की परिस्थितियां सेलिंग के लिए अनुकूल-मंत्री सारंग

मंत्री सारंग ने कहा कि भोपाल की झीलें सेलिंग, रोइंग, कयाकिंग और केनोइंग जैसे खेलों के लिए बेहद अनुकूल हैं। मध्य प्रदेश राज्य जल क्रीड़ा अकादमी वर्ष 2007 से खिलाड़ियों को तैयार कर रही है। अकादमी में सेलिंग, रोइंग, कयाकिंग, केनोइंग और स्लालम की सुविधाएं उपलब्ध हैं।अकादमी के खिलाड़ियों ने अब तक 28 अंतरराष्ट्रीय और 69 राष्ट्रीय पदक जीते हैं तथा 37 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। वर्ष 2025 की राजा भोज मल्टीक्लास सेलिंग चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश की टीम ने 8 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे।सारंग ने कहा कि भोपाल में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ा एक्सपोजर हैं। यहां स्थानीय प्रतिभाओं को देश के शीर्ष सेलर्स के साथ प्रतिस्पर्धा का अनुभव मिलता है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होने में मदद मिलती है।

होटल में युवक-युवती से पुलिसकर्मी बनकर वसूले 70 हजार

भोपाल पुलिस को हनीट्रैप जैसी साजिश की आशंका, केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठे

भोपाल (नप्र)। भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र के एक होटल में युवक-युवती के कमरे में कथित तौर पर पुलिसकर्मी बनकर घुसे चार लोगों ने उन्हें केस में फंसाने की धमकी देकर करीब 60 से 70 हजार रुपए वसूल लिए।

घटना के बाद शिकायत मिलने पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में मामला हनीट्रैप जैसी साजिश से जुड़ा होने की आशंका भी सामने आ रही है।

पिपलानी थाने से एसआई संतोष रघुवंशी के अनुसार घटना 3 अगस्त की शाम करीब 6 बजे की है। बरखेड़ी खुर्द निवासी युवक पिपलानी क्षेत्र स्थित एक होटल में युवती के साथ कमरे में था। इसी दौरान चार लोग कमरे में पहुंचे। आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और युवक-युवती से पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद उन्हें डराया-धमकाया और कार्रवाई करने की बात कही।

ट्विशा शर्मा केस

17 अगस्त तक चार्जशीट पेश करने का आदेश, गिरिबाला सिंह और समर्थ की न्यायिक हिरासत बढ़ी

भोपाल (नप्र)। मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में दोनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सुनवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट शोभना भलावे की अदालत में हुई। ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि दोनों आरोपियों की पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने वाली थी। सीबीआई ने इसे बढ़ाने के लिए आवेदन पेश किया और 19 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 17 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया।

शुभांग दीक्षित के अनुसार, सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और एजेंसी 19 अगस्त से पहले चार्जशीट पेश कर देगी। हालांकि अदालत ने सीबीआई को 17 अगस्त तक ही चार्जशीट पेश करने का निर्देश दिया है। यानी अब जांच एजेंसी को इसी तारीख तक चालान पेश करना होगा।

दतिया उपचुनाव की जीत ने बदलाव की राजनीति पर जनता की मुहर लगाई : जीतू पटवारी

छात्रों, किसानों, ओबीसी, महिलाओं और अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी कांग्रेस : हरीश चौधरी

भोपाल। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संगठन की आगामी रणनीति, राजनीतिक परिस्थितियों और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की तथा आगामी कार्यक्रमों एवं आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की।

बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी श्री हरीश चौधरी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी (चर्चुअल), प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी, राज्यसभा सांसद श्री विवेक तन्खा जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह जी, डॉ. गोविंद सिंह जी, सीडब्ल्यूसी सदस्य श्री कमलेश्वर पटेल जी, पूर्व मंत्री श्री कांतिलाल भूरिया जी, श्री सज्जन वर्मा जी, श्री बाला बच्चन जी, विजयलक्ष्मी साधो जी, श्री तरुण भनोट जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री एनपी प्रजापति जी, संगठन उपाध्यक्ष श्री सुखदेव पांसे जी, संगठन महासचिव श्री संजय कामले जी, महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा जी, विधायक श्री फूल सिंह बरैया जी, श्री विक्रांत भूरिया जी, श्री आरिफ मसूद जी, श्री घनश्याम सिंह जी, पूर्व विधायक श्री प्रवीण पाठक जी, श्री नीटू सिंह सिकरवार जी, श्री सत्यनारायण पटेल जी, सह-प्रभारी श्री रणविजय सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव श्री भूपेंद्र मरावी जी, हिना कावरे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अभय दुबे जी, NSUI प्रदेश अध्यक्ष श्री आशुतोष चौकसे जी, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीना बोरासी जी एवं सेवादल प्रदेश संगठक श्री अवनीश भार्गव जी सहित वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के पश्चात प्रदेश कांग्रेस प्रभारी श्री हरीश चौधरी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी एवं नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि पीएसी बैठक में संगठन सृजन अभियान और जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस युवाओं, छात्रों, किसानों, महिलाओं और ओबीसी वर्ग के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी।उन्होंने खाद संकट, उज्जैन के कथित भ्रष्टाचार, राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े विवाद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि लगभग पांच घंटे चली पीएसी बैठक में प्रदेश की राजनीतिक, संगठनात्मक और जनहित से जुड़ी परिस्थितियों पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने दतिया उपचुनाव में घनश्याम सिंह की जीत को कांग्रेस के साथ-साथ मध्य प्रदेश की जनता की जीत बताते हुए कहा कि दतिया ने बदलाव की राजनीति का स्पष्ट संदेश दिया है।

संपादकीय

छात्रसंघ चुनाव : प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष?

मध्यप्रदेश में नौ साल बाद कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की सुगबुगाहट के बाद इसकी प्रणाली को लेकर अभी से विवाद शुरू हो गया है। ये चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हों अथवा अप्रत्यक्ष प्रणाली से, इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को करना है, लेकिन प्रदेश के प्रमुख छात्र संगठनों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव कराने की मांग शुरू कर दी है। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग नवंबर 2024 में इसका ड्राफ्ट तैयार कर चुका है। सरकार एक कमेटी बनाकर इस ड्राफ्ट की समीक्षा करेगी।

कुछ बदलावों के साथ इसे लागू किया जा सकता है। प्रदेश में आखिरी बार छात्र संघ चुनाव 2017 में हुए थे, तब 6 विश्वविद्यालयों के 533 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव हुए थे। अब फिर से चुनाव शुरू हुए तो प्रदेश के 1400 से ज्यादा कॉलेज और 74 विश्वविद्यालयों के 14 लाख से अधिक छात्र अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगे। छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर पिछले साल जबलपुर हाई कोर्ट में छात्र अदनान अंसारी ने एक याचिका दायर की गई थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार और उच्च शिक्षा विभाग के रवैये पर नाराजगी जताई थी और 5 अगस्त को सरकार को सितंबर में चुनाव कराने की जानकारी देने को कहा था। कोर्ट ने सरकार से चुनाव की निश्चित तारीख, 2026-27 का शैक्षणिक कैलेंडर और पूरी कार्ययोजना पेश करने को कहा। इसके बाद सरकार ने सितंबर में चुनाव कराने की जानकारी हाईकोर्ट को दी। दरअसल इस मांग का एक आधार यह भी था कि विवि और कॉलेज छात्रों से छात्र संघ चुनाव की फीस तो वसूलते रहे, लेकिन सरकार ने उन्हें चुनाव कराने की अनुमति नहीं दी। अगर छात्र संघ चुनाव हुए तो असली सवाल यह है कि ये चुनाव किस प्रणाली से होंगे, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। आमतौर पर प्रत्यक्ष प्रणाली को ही वास्तविक चुनाव माना जाता है। हालांकि ऐसे चुनावो में शो बाजी, भारी खर्च और कभी कभी हिंसा भी हो जाती है। मप्र में एक प्रोफेसर की हत्या तक हो चुकी है। ऐसे में सरकार क्या निर्णय लेती है, यह देखने की बात है। बावजूद इसके छात्र संघ चुनावों का अपना महत्व है। राजनेताओं की नई पौध यहीं से तैयार होती है। युवाओं के राजनीतिक प्रशिक्षण की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है और उनकी सियासी नब्ज पकड़ने का भी अहम माध्यम है। अगर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू हुए तो इन्हें अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनावों और दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। राजनीतिक हल्कों में माना जा रहा है कि राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में जहां नियमित छात्रसंघ चुनाव होते रहे, वहां से सांसद-विधायक तक निकले, जबकि मध्य प्रदेश पिछड़ गया। हालांकि इसके नतीजे तुरंत नहीं दिखाई देंगे, लेकिन भविष्य की तैयारी की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। छात्र संघों के चुनाव नियमित रूप से होते रहने चाहिए, इस पर ज्यादातर लोगों की राय हां में ही हैं। लेकिन ये चुनाव शालीन तरीके से हों, ईमानदारी से हों और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए हों तो ज्यादा उचित होगा। हाल में जेन ज़ी के आंदोलनों से बता दिया है कि निर्वाचित छात्र संघों के अभाव में सरकार के पास यह जानने का कोई प्रभावी माध्यम नहीं है कि छात्रों की वाजिब समस्याएं क्या हैं और वो क्या चाहते हैं? कोई छात्रों और सरकार के बीच संवाद की कोई कड़ी नहीं है। दरअसल छात्रों का राजनीतिक रूझान में समाज की सोच में बदलाव को नापने का बैरोमीटर भी है। इसे सरकार को समझना होगा।

नजरिया

राज कुमार सिन्हा

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

पर्यावरण कानूनों की सर्वोच्चता का निर्णायक संदेश

भारत में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की बहस लंबे समय से चल रही है। सड़क, बांध, खनन, ताप विद्युत संयंत्र, औद्योगिक परियोजनाओं और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों जैसी बड़ी परियोजनाओं को आर्थिक विकास का आधार बताया जाता है, लेकिन इनके निर्माण से पहले पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन और संभावित नुकसान से बचाव भी कानून की अनिवार्य मांग है। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला पर्यावरणीय शासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

न्यायालय ने केंद्र सरकार के 7 जुलाई 2021 के उस कार्यालय ज्ञापन (ऑफिस मेमोरेंडम) को निरस्त कर दिया, जिसके जरिए उन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई थी, जो आवश्यक पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी हासिल किए बिना निर्माण या संचालन शुरू कर चुकी थीं। तीन सदस्यीय पीठ में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली शामिल थे। यह फैसला मूलतः इस सवाल से जुड़ा है कि क्या कार्यपालिका महज एक प्रशासनिक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से उस कानूनी व्यवस्था को बदल सकती है, जिसके तहत किसी परियोजना को शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट का उत्तर स्पष्ट है कि किसी वैधानिक व्यवस्था को महज प्रशासनिक आदेश के जरिए कमजोर या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत निर्धारित परियोजनाओं के लिए निर्माण शुरू करने अथवा परियोजना का विस्तार करने से पहले पर्यावरणीय स्वीकृति लेना आवश्यक है।

इसका उद्देश्य केवल सरकारी अनुमति हासिल करना नहीं है, बल्कि परियोजना के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का पहले से आकलन करना है। किसी बड़े बांध से कितने गांव प्रभावित होंगे, जंगल का कितना हिस्सा डूबेगा, नदी के प्रवाह और जैव-विविधता पर क्या असर पड़ेगा, खनन परियोजना से भूजल और कृषि भूमि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, औद्योगिक परियोजना से प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ सकता है अथवा किसी परमाणु परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय जोखिम क्या हैं। इन सभी सवालों का मूल्यांकन परियोजना शुरू होने से पहले होना चाहिए। यही पूर्व मूल्यांकन पर्यावरणीय कानूनों की मूल भावना है। यदि परियोजना पहले शुरू कर दी जाए और पर्यावरणीय मंजूरी बाद में मांगी जाए तो पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन अक्सर एक ऐसी स्थिति में होता है, जब नुकसान हो चुका होता है या परियोजना को रोकना व्यावहारिक और राजनीतिक रूप से कठिन बना दिया जाता है।

इसलिए 'पहले निर्माण, बाद में मंजूरी' की व्यवस्था पर्यावरणीय कानून के निवारक चरित्र को कमजोर करती है। 7 जुलाई 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऐसा कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसमें उन परियोजनाओं से संबंधित प्रक्रिया निर्धारित की गई थी जिन्होंने आवश्यक पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बिना निर्माण या संचालन शुरू कर दिया था। आलोचकों का तर्क था कि इस तरह की व्यवस्था से परियोजना संचालकों को गलत प्रोत्साहन मिलता है। यदि कोई कंपनी बिना मंजूरी के परियोजना शुरू कर देती है और बाद में जुर्माना, क्षतिपूर्ति अथवा कुछ शर्तों के साथ पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर सकती है, तो कानून का पूर्व-अनुमति वाला ढांचा कमजोर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिंदु पर हस्तक्षेप करते हुए 2021 के कार्यालय ज्ञापन को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने माना कि 2006 की पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना व्यवस्था में पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की जो वैधानिक आवश्यकता है, उसे केवल प्रशासनिक आदेश से बदला नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि केंद्र सरकार किसी भी परिस्थिति में पोस्ट-फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी की व्यवस्था नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि यदि विशेष परिस्थितियों में ऐसी व्यवस्था करनी है तो उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत वैधानिक अधिसूचना के माध्यम से किया जाना होगा। केवल कार्यालय ज्ञापन जारी करके वैधानिक पर्यावरणीय व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता है।

यानी अदालत ने कार्यपालिका की शक्ति को पूरी तरह समाप्त नहीं किया, बल्कि उसके इस्तेमाल के लिए संवैधानिक और वैधानिक रास्ता स्पष्ट किया है। यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि भविष्य में यदि केंद्र सरकार किसी विशेष परिस्थिति में ऐसी व्यवस्था करना चाहती है तो उसे पारदर्शी, वैधानिक और विधि-सम्मत प्रक्रिया अपनानी होगी। प्रशासनिक स्तर पर जारी एक साधारण कार्यालय आदेश के जरिए पर्यावरण कानून की मूल शर्त को कमजोर नहीं किया जा सकता है।

पर्यावरणीय कानूनों में बार-बार ऐसी व्यवस्थाएं सामने आती रही हैं जिनमें नियमों का उल्लंघन कर चुकी परियोजनाओं को बाद में नियमित करने का रास्ता उपलब्ध कराया जाता है। इससे एक गंभीर सवाल उठता है कि जो परियोजना कानून का पालन करके आगे बढ़ी और जिसने पर्यावरणीय स्वीकृति की लंबी प्रक्रिया पूरी की, उसकी तुलना में नियमों का उल्लंघन करने वाली परियोजना को बाद में राहत देना क्या न्यायसंगत है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल एक कार्यालय ज्ञापन को निरस्त करने तक सीमित नहीं है। यह शासन-व्यवस्था को यह संदेश देता है कि पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन करके परियोजना खड़ी करना कोई सामान्य प्रशासनिक कमी नहीं माना जा सकता। इस फैसले का महत्व मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में और बढ़ जाता है, जहां बड़े बांध, खनन, ताप विद्युत, औद्योगिक परियोजनाओं तथा प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर पर्यावरणीय और सामाजिक विवाद सामने आते रहे हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के मामले में पर्यावरणीय प्रभाव का प्रश्न केवल भूमि उपयोग तक सीमित नहीं होता। जल संसाधन, जैव-विविधता, तापीय प्रभाव, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, आपदा प्रबंधन, स्थानीय समुदायों की सुरक्षा और दीर्घकालिक पर्यावरणीय जोखिम जैसे प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार बड़े बांधों में जंगल, नदी, कृषि भूमि, मछली संसाधन, वन्यजीव और विस्थापन जैसे अनेक प्रभाव जुड़े होते हैं। खनन परियोजनाओं में भूजल, वन क्षेत्र, कृषि और स्थानीय आजीविका प्रभावित हो सकती है।

ऐसी परियोजनाओं में यदि पहले निर्माण शुरू हो जाए और पर्यावरणीय स्वीकृति बाद में मिले तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की पूरी अवधारणा ही कमजोर पड़ सकती है। अक्सर पर्यावरणीय मंजूरी को विकास परियोजनाओं में एक प्रशासनिक बाधा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन वास्तविकता में पर्यावरणीय मंजूरी का उद्देश्य परियोजना को रोकना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विकास पर्यावरणीय सीमाओं और कानूनी मानकों के भीतर हो। भारत के संविधान में भी पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की न्यायिक व्याख्या स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार तक पहुंच चुकी है। वहीं अनुच्छेद 48-ए राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का दायित्व देता है। इस दृष्टि से पर्यावरणीय कानून विकास-विरोधी नहीं हैं। वे विकास को अधिक जिम्मेदार, टिकाऊ और भविष्य की पीढ़ियों के हित में बनाने का माध्यम हैं। भारत में कई बार यह धारणा बनाई जाती है कि कोई परियोजना एक बार शुरू हो जाए तो उसे बंद करना कठिन है, क्योंकि उसमें भारी निवेश हो चुका होता है और उससे रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियां जुड़ जाती हैं।लेकिन यदि यही तर्क स्वीकार कर लिया जाए तो कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या कंपनी को उस व्यक्ति से अधिक लाभ मिल सकता है जिसने शुरुआत से कानून का पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महत्व इसी जगह है। न्यायालय ने संकेत दिया है कि किसी परियोजना में निवेश हो जाना अपने आप में पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन का लाइसेंस नहीं बन सकता है। किसी परियोजना का आर्थिक महत्व अपनी जगह है, लेकिन पर्यावरणीय कानूनों का पालन उससे पहले की शर्त है।भविष्य की सरकारों के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि इस फैसले का एक व्यापक संवैधानिक महत्व है।

सरकारें नीतियां बना सकती हैं, प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकती हैं और विकास परियोजनाओं के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकती हैं। लेकिन जब किसी वैधानिक अधिसूचना द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

इसलिए भविष्य में यदि केंद्र सरकार किसी विशेष श्रेणी की परियोजनाओं के लिए पोस्ट-फैक्टो मंजूरी या किसी प्रकार की 'एमनेस्टी' व्यवस्था लाना चाहती है तो उसे उचित वैधानिक अधिसूचना के माध्यम से ऐसा करना होगा। महज एक कार्यालय ज्ञापन पर्याप्त नहीं होगा। यह बात पर्यावरणीय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को मजबूत कर सकती है। फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि न्यायालय ने इसे इस तरह लागू नहीं किया है कि पहले से जारी मंजूरियों और चल रही परियोजनाओं में अचानक व्यापक व्यवधान पैदा हो। इसलिए 2021 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर पहले से दिए गए पर्यावरणीय स्वीकृति मामलों को लेकर फैसले का प्रभाव अलग तरीके से निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण की वास्तविक परीक्षा इसके बाद शुरू होती है।

अब केंद्रीय और राज्य सरकारों, पर्यावरण मंत्रालयों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा संबंधित नियामक संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई परियोजना आवश्यक पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना निर्माण या संचालन शुरू न करे। सिर्फ कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। उसकी निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही आवश्यक है।

स्थानीय समुदायों, ग्राम सभाओं, पर्यावरण संगठनों और प्रभावित नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। किसी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों की वास्तविक जानकारी अक्सर उन्हीं समुदायों के पास होती है जो उसके आसपास रहते हैं। इसलिए पर्यावरणीय निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भागीदारी और सूचना तक उनकी पहुंच को मजबूत करना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत के पर्यावरणीय कानूनों के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और नीतिगत संदेश लेकर आया है। पर्यावरणीय स्वीकृति कोई औपचारिकता नहीं है जिसे परियोजना शुरू होने के बाद पूरा किया जा सके। इसका उद्देश्य ही यह सुनिश्चित करना है कि पर्यावरणीय नुकसान की आशंका का आकलन नुकसान होने से पहले किया जाए और आवश्यक सुरक्षा उपाय परियोजना शुरू होने से पहले तय किए जाएं। आने वाले समय में इस फैसले की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि सरकारें और परियोजना प्राधिकरण इसे केवल न्यायिक आदेश के रूप में देखते हैं या विकास की पूरी प्रक्रिया में पर्यावरणीय जवाबदेही के अनिवार्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं। कानून का अर्थ यही है कि विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं, बल्कि पर्यावरणीय न्याय और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए हो।

सामयिक

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

दुनिया में बढ़ता शरणार्थी संकट

इस वक्त स्पेन 60 हजार घुसपैठी शरणार्थी संकट से जूझ रहा है। ये शरणार्थी मोरक्को और उप सहारा अफ्रीका से झुंडों में समुद्र के रास्ते आकर स्पेन के सेउटा और मेलिला में पहुंचे हैं। दरअसल स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने जून-2026 के अंत में एक फैसला दिया था कि स्पेन पहुंचने वाले प्रवासियों को बिना कानूनी प्रतिक्रिया के तत्काल वापस नहीं लौटाया जाए। इस फैसले को सोशल मीडिया पर अनुचित एवं मनमाने तरीके से प्रस्तुत किया गया है। नतीजतन इंटरनेट पर यह अफवाह फैल गई कि स्पेन ने अपनी सीमाएं शरणार्थियों के लिए पूरी तरह खोल दी है। वहां पहुंचने वालों को बलपूर्वक वापिस नहीं किया जाएगा। इसके बाद मोरक्का और अफ्रीका के करीब 60 हजार लोग संगठित होकर समुद्र में स्पेन जाने के लिए उतर गए और 24 से 48 घंटों के भीतर तैरकर या पैदल चलकर स्पेन की सीमा में घुस गए। दरअसल इस्लाम बहुल इन अफ्रीकी देशों में युवाओं के लिए सीमित रोजगार के अवसर हैं, इसलिए एक बड़ा समूह एक झटके में ही पलायन कर गया। इस संकट के कारण स्पेन से इटली और अमेरिका ने स्पेन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि ऐसे नियमों से यूरोप में अवैध प्रवासी शरणार्थी के रूप में घुसते रहेंगे। यूरोपीय संघ के 22 देषों ने एक पत्र लिखकर इस नीति की कड़ी आलोचना की है, बावजूद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अपने सहयगियों की इस प्रतिक्रिया को पक्षपातपूर्ण बताया है। हालांकि भविष्य में ऐसी घुसपैठ को राकने के लिए स्पेन ने अपनी समुद्री सीमा पर फ्लोटिंग बेरियर लगाना षुरू कर दिया है।

इस समय यूक्रेन-रूस, इजरायल-हमास और अमेरिका एवं ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण शरणार्थी समस्या सुरसामुख की तरह फैलती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में षरणार्थियों के मामलों से जुड़े 'यूनाइटेड नेषन्स हाई कमिशनर और रिफ्यूजी' (यूएनएचसीआर) की ग्लोबल ट्रेंडस रिपोर्ट्स ने खुलासा किया है कि युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण 11 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। यह हमारी वैश्विक स्थिति पर कलंक है। 2022 में करीब 1.9 करोड़ लोग विस्थापित हुए, जिनमें से 1.1 करोड़ से अधिक लोगों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रामण के चलते अपना घर छोड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग जंग के कारण विस्थापित हुए हैं। यह आपात स्थिति का संकेत है। कुछ समय के भीतर ही 35 प्रकार की आपात स्थितियां सामने आई हैं, जो बीते कुछ सालों की तुलना में तीन से चार गुना अधिक हैं। इनमें से कुछ ही मीडिया की सुर्खियां बनी, बांकी नजरअंदाज कर दी गई। सूडान से पश्चिमी नागरिकों को निकाले जाने के बाद वहां हो रहे संघर्ष की खबर अधिकांश अखबारों से गायब हैं। सूडान में इस संघर्ष के चलते अप्रैल 2023 के बाद से अब तक 20 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं कांगो गणराज्य, इथोपिया और म्यांमा में संघर्श के चलते करीब 10-10 लाख लोग अपने मूल आवास और देश छोड़ने को विवश हुए थे।

बीती एक शताब्दी में इतनी तेज गति से कहीं भी पलायन देखने में नहीं आया, जितना कि यूक्रेन युद्ध के बाद मोरक्को और अफ्रीका में देखने में आया है। विश्व बैंक के मुताबिक 2020 के अंत में यूक्रेन की आबादी 4.4 करोड़ थी। एनएचसीआर ने आशंका जताई है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो 40 लाख से भी ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। युद्ध शरणार्थियों ने इससे पहले 2011 में सीरिया में छिड़े गृहयुद्ध के चलते बड़ी संख्या में पलायन का सिलसिला शुरू हुआ था। अमेरिका ने अपने मित्र देश ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर सीरिया पर मिसाइल हमला बोला था। सीरिया में मौजूद रासायनिक हथियारों के भंडारों को नष्ट करने के मकसद से 105 मिसाइलें दागी गईं थीं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ये मिसाइलें राजधानी दमिश्क और होम्स शहरों पर बरसाई गई थी। इसमें रासायनिक हथियारों के भंडार और वैज्ञानिक शोध केंद्रों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों के परिणामस्वरूप कई इमारतों में आग लग गई थी। दमिश्क धुएं के गुबार से ढक गया था। ऐसे ही दृश्य हम आजकल यूक्रेन में रूसी हमले के परिणामस्वरूप देखने में आ रहे हैं। हमले में कितनी जनहानि हुई थी, यह तो आज तक तय नहीं हुई, लेकिन सीरिया ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। वहीं रूस, चीन और ईरान ने कड़ा विरोध जताया था। इनका कहना था कि पहले रासायनिक हथियार रखने और उनका इस्तेमाल किए जाने तथा किसके द्वारा इस्तेमाल किए गए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी? अमेरिका ने ईराक पर भी जैविक एवं रासायनिक हथियारों की उपलब्धता संबंधी आशंका के चलते हमला बोला थ। लेकिन बयानबाजी से इतर युद्ध रोकने की ठोस पहल किसी देश ने नहीं की थी।

करीब साढ़े सात साल चले सीरिया के युद्ध में पांच लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। एक करोड़ लोगों ने तत्काल शरणार्थी के रूप में विस्थापन का दंश झेला, इनमें से 67 लाख आज भी अनेक देशों में शरणार्थी बने हुए हैं। ये शरणार्थी जिन देशों में रह रहे हैं, उनमें भी अपनी इस्लामिक कट्टरता के चलते संकट का सबब बने हुए हैं। जर्मनी ने सबसे ज्यादा विस्थापितों को शरण दी थी। अब यही जर्मनी इनके धार्मिक कट्टर उन्माद के चलते रोजाना नई-नई परेशानियों से रूबरू हो रहा है।

दुनिया उन लोगों के आंकड़ों पर गौर कर रही है, जिन्होंने पड़ोसी देशों में शरण ली हुई है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि प्रभावित लोगों की सबसे बड़ी संख्या यूक्रेन और स्पेन के भीतर अभी मौजूद है। हालांकि इन विस्थापि नागरिकों के कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं है। एनएचसीआर का अनुमान है कि युद्धरथ देशों में लाखों लोग देश के भीतर ही विस्थापन का दंश और दहशत झेलने को विवश हैं, जो फिलहाल रेल, बस, कार या बंकरों में रहते हुए प्राण बचाने की कोशिश में लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की वैश्विक रिपोर्ट की मानें तो 20 साल पहले की तुलना में विस्थापन का संकट दोगुना बढ़ गया है। 2019 तक आंतरिक रूप से विस्थापितों की कुल संख्या 4 करोड़ 13 लाख थी। इनमें से 1 करोड़ 36 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्हें 2018 में ही विस्थापन का दंश झेलना पड़ा था। यह सही है कि विकसित या पूंजीपति देश अपने वर्चस्व के लिए युद्ध के हालात पैदा करते हैं, जैसा कि हम यूक्रेन और ईरान के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका और रूस के वर्चस्व की लड़ाई देख रहे हैं। ये वही देश हैं, जिन्होंने 1993 तक तीसरी परमाणु शक्ति रहे देश यूक्रेन को 1994 में बुडापेस्ट परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कराकर उसके सभी परमाणु हथियार समुद्र में नष्ट करा दिए थे। अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को इस समझौते के लिए राजी किया था और इन्हीं देशों के साथ रूस ने भी सहमति जताते हुए यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी ली थी। लेकिन अब रूस ने सीधा यूक्रेन पर हमला बोल दिया और अमेरिका व ब्रिटेन दूर खड़े रहकर न केवल तमाशा देख रहे हैं, बल्कि उसे उकसाकर पूरी तरह बर्बादी के कगार पर पहुंचाने का कुत्सित काम भी कर रहे है।

बावजूद यही वह अमीर देश हैं, जो सबसे ज्यादा युद्ध व पर्यावरण षरणार्थियों को षरण देते हैं। 2015 में सीरिया में जो हिंसा भड़की थी, उससे बचने के लिए लाखों लोगों ने जान जोखिम में डालकर भूमध्य सागर को महिलाओं व बच्चों के साथ पार किया और ग्रीस एवं इटली में शरण ली थी। स्पेन ने भी 60 हजार लोगों को हाल ही में शरण दी हुई है। इन तीनों देशों ने तब कहा था कि समय के मारे षरणार्थियों को आश्रय देने की नीति बनाई जाना आवश्यक है। वेनेजुएला में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के चलते चालीस लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन किया था। इनमें से बमुश्किल पांच लाख लोग ही औपचारिक शरणार्थियों के दर्जे में हैं। युद्ध एवं गृहयुद्ध के हालातों के चलते सबसे ज्यादा सीरिया के 67 लाख, अफगानिस्तान के 27 लाख, दक्षिण सूडान के 23 लाख, म्यांमार के 11 लाख और सोमालिया के 9 लाख लोग शरणार्थियों के रूप में विभिन्न विकसित देशों के सीमांत इलाकों में शरण लिए हुए हैं। भारत में बांग्लादेश और म्यांमार के गृहयुद्ध से पलायन किए करीब चार करोड़ लोगों ने घुसपैठ की हुई है। भारत इनकी धार्मिक कट्टरता का संकट भी झेल रहा है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

सचिन सिंह परिहार

लेखक व्यंग्यकार हैं।

नई पीढ़ी समय की सबसे बड़ी अपराधी

नई पीढ़ी बड़ी अपराधी है। इसका सबसे बड़ा अपराध यह है कि इसका जन्म समय पर नहीं हुआ। अगर यह बीस पच्चीस साल पहले पैदा हो जाती, तो इसे मालूम होता कि देश कैसा था, सड़क कैसी थी, ट्रेन कैसी थी, नेता कैसे थे और जनता कैसी थी। लेकिन इस पीढ़ी ने बड़ी धृष्टता की, यह 1997 के बाद पैदा हो गई। अब इसे क्या पता कि इतिहास किसे कहते हैं और राजनीति किसे।

आज का लड़का मोबाइल से यूपीआई कर देता है। उसे लगता है कि दुनिया में हमेशा से ऐसा ही होता होगा। उसे कौन समझाए कि कभी दस रुपये का छुट्टा न मिलने पर दुकानदार दो टॉफी पकड़ाकर राष्ट्रनिर्माण में योगदान दे देता था। वह पूछता है, 'QR कोड कहाँ है?' उसे क्या मालूम कि एक समय पूरा देश 'छुट्टा है क्या?' के सिद्धांत पर चलता था।

नई पीढ़ी वातानुकूलित वंदे भारत में बैठकर सोचती है कि ट्रेन का मतलब यही होता है। उसे कौन बताए कि कभी ट्रेन में चढ़ना भी एक योगासन था। आरक्षण होने के बाद भी सीट मिले, यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। शौचालय में जाना अपने साहस का प्रमाण देना था। पटरियों पर जो कुछ गिरता था, उसे देखकर प्रकृति भी आँखें बंद कर लेती थी। अब बच्चे पूछते हैं, 'सच में ऐसा होता था?' उन्हें लगता है कि दादा जी विज्ञान कथा सुना रहे हैं।

राजनीति का भी बड़ा संकट है। जिसने केवल एक दौर देखा है, वह उसी को सामान्य मान बैठता है। जिस बच्चे ने बचपन से डिजिटल भुगतान देखा, उसे नकद की लाइनें कहानी लगती हैं। जिसने मेडिकल कॉलेजों, एक्सप्रेसवे, नए पुल और नई योजनाओं की चर्चा सुनी, वह पूछ बैठता है, 'पहले क्या था?' और यहीं से दोनों पक्षों का रक्तचाप बढ़ जाता है।

एक पक्ष कहता है, 'बेटा, पहले कुछ नहीं था।' दूसरा कहता है, 'बेटा, पहले सब कुछ था।' बेचारा बेटा सोचता है कि शायद देश 2014 से पहले मंगल ग्रह पर था और बाद में पृथ्वी पर आया, या फिर इसके ठीक उल्टा हुआ होगा। इतिहास किताबों में कम और व्हाट्सऐप विश्वविद्यालय में ज़्यादा पढ़ाया जाने लगा है।

हमारे यहाँ हर सरकार अपने कामों की सूची ऐसे सुनाती है, जैसे शादी में मिठाइयों का मेन्यू पढ़ा जा रहा हो। मेडिकल कॉलेज, हाईवे, पुल, डिजिटल भुगतान, शौचालय, रेलवे स्टेशन, मंदिर, सुरंग, विश्वविद्यालय, योजनाएँ। सूची इतनी लंबी होती है कि सुनने वाला भूल जाता है कि शुरुआत किससे हुई थी। उधर विपक्ष भी कम नहीं। वह घोटालों की सूची निकालता है। 2G, कोयला, कॉमनवेल्थ, हेलीकॉप्टर। दोनों पक्ष सूचियाँ पढ़ते हैं और जनता बीच मे कैलकुलेटर लेकर बैठी रहती है कि आखिर उसके हिस्से में आया क्या।

नई पीढ़ी की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह सवाल पूछती है। 'हमारे लिए क्या किया?' बस, इतना पूछना भर है कि दोनों तरफ़ के प्रवक्ता उसे राष्ट्रभक्त या राष्ट्रद्रोही घोषित करने की तैयारी कर लेते हैं। कोई यह नहीं कहता कि बेटा, बैठो, आराम से बात करते हैं। सब कहते हैं, पहले हमारा वीडियो देखो, फिर निर्णय लेना।

अब राजनीति का हाल क्रिकेट जैसा हो गया है। अगर आपकी टीम जीत गई तो कप्तान महान। हार गई तो पिच खराब, अंपायर पक्षपाती और मौसम षड्यंत्रकारी। समर्थक चाहते हैं कि इतिहास केवल उनकी सरकार से शुरू हो। विरोधी चाहते हैं कि इतिहास उनकी सरकार पर समाप्त हो। दोनों को वर्तमान से ज़्यादा अतीत और भविष्य की चिंता है।

नई पीढ़ी बेचैन है। उसे नौकरी भी चाहिए, अच्छी शिक्षा भी, सुरक्षित जीवन भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी और तेज़ इंटरनेट भी। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा मिलता है, भाषण। हर चुनाव में उसे बताया जाता है कि वह देश का भविष्य है। चुनाव खत्म होते ही वही भविष्य अगले चुनाव तक प्रतीक्षा सूची में डाल दिया जाता है।

असली विडंबना यह नहीं कि नई पीढ़ी को पुराना भारत नहीं पता। विडंबना यह है कि पुरानी पीढ़ी भी अपने समय को निष्पक्ष होकर याद नहीं करना चाहती। स्मृति भी अब दलों में बँट गई है। एक स्मृति में केवल अंधेरा है, दूसरी में केवल उजाला। जबकि सच यह है कि हर दौर में कुछ उपलब्धियाँ थीं, कुछ असफलताएँ थीं, कुछ ईमानदार लोग थे, कुछ अवसरवादी भी।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि कोई नेता महान है या कोई विपक्ष निकम्मा। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि नागरिक प्रश्न पूछ सके और उत्तर भी सुन सके। अगर नई पीढ़ी केवल जयकारा लगाए, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। अगर वह केवल विरोध करे, तब भी लोकतंत्र कमजोर होगा। लोकतंत्र तब मजबूत होगा, जब वह उपलब्धियों को स्वीकार करे, कमियों पर सवाल करे और किसी भी नेता को भगवान या शैतान बनाने से इंकार कर दे।

इसलिए नई पीढ़ी का असली अपराध यह नहीं कि उसने केवल एक शासन देखा है। उसका अपराध यह है कि वह हर बात का प्रमाण मांगती है। और हमारे यहाँ प्रमाण से ज़्यादा भावनाएँ उपलब्ध हैं। आँकड़ों से ज़्यादा नारे हैं। इतिहास से ज़्यादा प्रचार है। शायद इसी कारण हर चुनाव से पहले देश को फिर से बताया जाता है कि स्वर्ग कब शुरू हुआ था और नरक कब समाप्त हुआ था। जनता चुपचाप मुस्कराती है। उसे मालूम है कि सरकारें बदलती रहती हैं, घोषणाएँ बदलती रहती हैं, पोस्टर बदलते रहते हैं। नहीं बदलता तो बस नागरिक का वह प्रश्न, 'अच्छा, आगे क्या? '

मुद्दा

प्रभुनाथ शुक्ल

लेखक पत्रकार हैं।

मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल

पत्रकारिता और बदलते दौर का सच एक आम विमर्श का मुद्दा बन गया है। अमूमन यह देखा जा रहा है कि आमतौर पर देश के ज्वलंत मुद्दों पर सत्ता और संस्थाओं पर सवाल उठाने के बजाय सबसे पहले मीडिया को घेरे में लिया जाता है और उसकी विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो जाता है और उसे कठघरे में खड़ा किया जाता है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता, उसके दायित्व और लोकतंत्र में उसकी भूमिका पर गंभीर विमर्श करना आवश्यक है।

लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। सत्ता चाहे किसी भी दल की हो, पत्रकारिता का मूल दायित्व सत्ता का गुणगान करना नहीं, बल्कि जनता के सवालों को सामने लाना और शासन-प्रशासन से जवाब मांगना है। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उन कार्यों को भी समाज के सामने रखें सिर्फ नैरेटिव के तहत सरकारों को बदनाम करना यह पत्रकारिता नहीं है। हां लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार लोकहित संरक्षण के लिए सबसे पहले जवाब दे है।

लेकिन बदलते दौर में पत्रकारिता और सत्ता के बीच संबंधों को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह चिंता लगातार सामने आ रही है कि पत्रकारों और पत्रकारिता के खिलाफ एक नकारात्मक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। सत्ता के पक्ष में लिखने-बोलने वाले पत्रकारों को सम्मान और मंच मिलना तथा जमीनी मुद्दों और सरकार से असहज सवाल पूछने वाले पत्रकारों को कानूनी कार्रवाई, दबाव या विवादों का सामना करना। लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं कहा जा सकता।

हाल में झारखंड में पत्रकार अमन चोपड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर का मामला भी इसी बहस का हिस्सा बन गया है। मैं यह दावा नहीं कर रहा कि अमन चोपड़ा किस विचारधारा के समर्थक हैं या किस राजनीतिक विचार के पक्षधर हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वे एक पत्रकार हैं और यदि उन्होंने झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन की कवरेज की है, तो सवाल यह भी उठता है कि उनके खिलाफ ही एफआईआर क्यों दर्ज की गई? क्या उसी आंदोलन की कवरेज करने वाले अन्य पत्रकारों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई हुई? यदि नहीं हुई तो ऐसा अंतर क्यों? यह सवाल किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन का नहीं, बल्कि पत्रकारिता के अधिकार और समान मानदंड का है।

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी सरकार का न तो समर्थक हूं और न विरोधी। मेरा मानना है कि पत्रकारिता का काम सत्ता के पक्ष या विपक्ष में खड़ा होना नहीं, बल्कि तथ्यों के पक्ष में खड़ा होना है। जो खबर है, वह खबर के रूप में सामने आनी चाहिए। पत्रकार को भी किसी राजनीतिक या वैचारिक पूर्वाग्रह से मुक्त होकर घटनाओं की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। लेकिन यदि कोई पत्रकार तथ्यात्मक और निष्पक्ष तरीके से किसी आंदोलन, प्रदर्शन या जनसमस्या को सामने रखता है, तो केवल उसकी रिपोर्टिंग के आधार पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सवाल निश्चित रूप से विचारणीय है। हालांकि उसने कुछ निर्धारित नैरेटिव के तहत अगर रिपोर्टिंग की गई है यह गलत है हम इसका समर्थन नहीं करते हैं।

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून क्यों नहीं?

आज आवश्यकता इस बात की है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में पत्रकारों की सुरक्षा तथा उनकी पेशेवर स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चर्चा हो। पत्रकारों को खबरों की रिपोर्टिंग करते समय भयमुक्त वातावरण मिले, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

यदि किसी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, तो यह देखा जाना चाहिए कि मामला वास्तव में आपराधिक कृत्य का है या पत्रकार द्वारा की गई रिपोर्टिंग और अभिव्यक्ति से जुड़ा है। पत्रकार गलत हो तो कानून अपना काम करे, लेकिन केवल असहमति, आलोचना या रिपोर्टिंग के कारण पत्रकार को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े, तो यह चिंता का विषय है।

मेरी राय में देश में ऐसा स्पष्ट कानूनी ढांचा होना चाहिए जिसमें पत्रकारों की पेशेवर स्वतंत्रता की रक्षा हो और साथ ही पत्रकारिता की आड़ में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी निष्पक्ष कार्रवाई का रास्ता खुला रहे। यानी स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही और अधिकार के साथ जिम्मेदारी, दोनों का संतुलन जरूरी है।

वैश्विक रैंकिंग से आगे भी बड़ा सवाल

भारत में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर वैश्विक स्तर पर जारी होने वाली विभिन्न रैंकिंग और रिपोर्टों पर बहस होती रही है। इन रैंकिंग के आकलन और मानकों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इससे उस मूल सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि क्या देश में पत्रकार अपने सवाल पूछने और जमीनी हकीकत दिखाने के लिए पर्याप्त रूप से स्वतंत्र महसूस करते हैं?

पत्रकारों के साथ मारपीट, धमकी, दबाव या कानूनी विवादों की घटनाएं जब सामने आती हैं तो स्वाभाविक रूप से मीडिया की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। सत्ता चाहे केंद्र में हो या राज्य में, उसे ऐसे मामलों में अधिक संवेदनशील और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

सत्ता बदले तो नजरिया भी बदलना चाहिए

सत्ता में बैठे लोगों को यह समझना होगा कि आज की सत्ता कल विपक्ष में हो सकती है और आज विपक्ष में बैठा व्यक्ति कल सत्ता में आ सकता है। इसलिए मीडिया की स्वतंत्रता का सवाल किसी एक दल या सरकार का सवाल नहीं है। यह व्यवस्था और लोकतंत्र का सवाल है। आपने कई मुद्दे ऐसे देखे होंगे जब पत्रकार किसी नेता से सवाल पूछता है तो कुछ नेता ऐसे हैं जो उल्टा उससे ही सवाल करने लगते हैं। उसकी पत्रकारिता के सवाल पर उसकी जाति और धर्म तक उतर आते हैं।

यदि आज किसी पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई को इसलिए उचित ठहराया जाता है क्योंकि वह सरकार के पक्ष में नहीं लिख रहा, तो कल वही तर्क किसी दूसरी सरकार के समय किसी दूसरे पत्रकार के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र के हित में जरूरी है कि पत्रकारिता के लिए समान और निष्पक्ष मानदंड तय हों।

दिल्ली में विभिन्न आंदोलनों और प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों के खिलाफ कितने मामले दर्ज हुए, इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। यह भी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि ऐसे मामले हुए या नहीं हुए। लेकिन यदि किसी पत्रकार के खिलाफ केवल उसकी पत्रकारिता के कारण एफआईआर दर्ज की गई है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसी कार्रवाई का समर्थन नहीं करता।

सोशलमीडिया ने मुख्यधारा की पत्रकारिता को दी चुनौती। मीडिया के बदलते स्वरूप को भी समझना जरूरी है। मुख्यधारा की मीडिया अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन सोशलमीडिया ने समाचारों के प्रसार और उपभोग का पूरा ढांचा बदल दिया है।

दिल्ली, झारखंड के छात्र आंदोलन से लेकर देश के विभिन्न आंदोलनों और जनमुद्दों तक, सोशलमीडिया ने कई बार ऐसे विषयों को व्यापक मंच दिया जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया में अपेक्षित जगह नहीं मिल सकी। इसका परिणाम यह है कि बड़ी संख्या में लोग अब सोशलमीडिया के माध्यम से खबरें देख और समझ रहे हैं।

यह मुख्यधारा की पत्रकारिता के लिए एक चुनौती भी है और आत्ममंथन का अवसर भी।

लोगों का भरोसा किसी एक माध्यम से नहीं, बल्कि सच्ची, तथ्यपूर्ण और निष्पक्ष पत्रकारिता से बनता है। यदि किसी मीडिया संस्था को लगता है कि उसकी खबरों पर जनता का भरोसा कम हो रहा है, तो उसे यह विचार करना होगा कि कहीं वह सत्ता, बाजार, विचारधारा या संस्थागत दबाव के बीच अपनी मूल पत्रकारिता से तो दूर नहीं हो रही।

पत्रकारिता का भविष्य किसके साथ है?

पत्रकारिता किसी सत्ता, दल या विचारधारा की निजी संपत्ति नहीं है। पत्रकारिता जनता की आवाज है। सत्ता से सवाल पूछना पत्रकारिता का अपराध नहीं, बल्कि उसका लोकतांत्रिक दायित्व है। उसी तरह पत्रकार का भी दायित्व है कि वह खबर को तथ्य, प्रमाण और निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करे।

हमें ऐसी पत्रकारिता चाहिए जो न सत्ता की आंखों पर पट्टी बांधे और न विपक्ष के प्रति आंखें बंद करे। जो सरकार अच्छा काम करे, journalist.pankaj@gmail.com उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और जहां सवाल हों, वहां सवाल भी उठने चाहिए। पत्रकारिता का असली पक्ष सत्ता या विपक्ष नहीं, बल्कि सत्य होना चाहिए।

यदि किसी पत्रकार ने कानून का उल्लंघन किया है तो जांच और कार्रवाई कानून के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन यदि केवल उसकी पत्रकारिता, रिपोर्टिंग या असहमति के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो उस पर सवाल उठना भी लोकतांत्रिक अधिकार है।

सत्ता को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है और पत्रकारिता को भी आत्ममंथन की। दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर न हो। क्योंकि अंततः सवाल सिर्फ एक पत्रकार का नहीं है। सवाल यह है कि क्या आने वाली पीढ़ियों के पत्रकार बिना भय के सवाल पूछ पाएंगे? और यदि पत्रकार सवाल पूछने से डरने लगे, तो फिर लोकतंत्र में जनता के सवाल कौन पूछेगा?

पुस्तक चर्चा

राकेश सोहम्

समीक्षक

रोजमर्रा की विसंगतियों पर छोटे और रोचक व्यंग्य

व्यंग्य लेखन एक सामाजिक उपक्रम है। यदि व्यंग्य समाज के लिए नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। व्यंग्य व्यक्तिगत शिकवा शिकायत नहीं है, न ही वह मनोरंजन का साधन है। व्यंग्यकार अन्याय और अनीति के विरुद्ध समाज की पीड़ा को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। यही बानगी इस किताब की व्यंग्य रचनाओं में दिखाई देती है। सभी रचनाएं रोजमर्रा के जीवन में आने वाली विसंगतियों को लेकर सरल भाषा और सहज हास्य (छोटेलाल 'अनमने' होलटाइम कवि हैं, 24 गुणा 7 वाले - कवि की भार्या से) को लेकर चलती हैं। पाठक इन्हें पढ़कर मुस्कुराते हैं। विसंगतियों से दो-चार होने की सोच के साथ खड़े होते है। दरअसल, इस किताब के लेखक, 87 वर्षीय कुन्दन सिंह परिहार के पास जीवन का एक लंबा अनुभव है।

किताब की छपाई आकर्षक है। प्रकाशित रचनाओं का फॉन्ट साइज़ ऐसा है जो आंखों में तनाव नहीं आने देता। छोटी और हल्की-फुल्की रचनाएं आधुनातन आपाधापी में व्यस्त पाठकों को पसंद आएंगी। इस किताब को चटपट पढ़ा जा सकता है। रचनाओं के विषय हमारे आसपास के हैं (खुदगर्जी, नैतिकता, किराएदार, कुंभ, राजनीति, समाज) जो इन्हें सदाबहार व्यंग्य रचनाओं की श्रेणी में रखते हैं। कुन्दन सिंह परिहार को लगभग 20 साल तक व्यंग्य पुरोधा हरिशंकर परसाई जी के आवास के बहुत नजदीक रहने का मौका मिला है। इसलिए उनकी रचनाओं में परसाई की भाषा शैली दिखाई देती है।

सहज हास्य से निकले तीखे व्यंग्य 'गुस्ताख हंसी' में देश के बड़े कारोबारियों ने सरकार को एक पत्र भेजा है। जिसमें कारोबारियों ने लिखा है कि वह इस बात से बहुत दुखी हैं कि उन्हें जिंदगी में मुश्किल से हंसने का मौका मिलता है, जबकि मामूली हैसियत वाले खुलकर हंसते हैं। इस रचना का मजेदार अंत देखिए। सरकार के पास इस दरख्वास्त के पहुंचते ही धड़ाधड़ कार्यवाही शुरू हो गई और आदेश निकल गया कि सामान्य लोग अपनी हंसी पर काबू रखें और हैसियतदारों के बंगलो के पास से गुजरते हुए जोर से हंसने की गुस्ताखियां ना करें। इसका उल्लंघन करने वालों के लिए सजा मुकर्रर की जाएगी।

कुल 152 पृष्ठों के इस व्यंग्य संकलन में छोटी-बड़ी 49 व्यंग्य रचनाएँ हैं। रचनाओं के शीर्षक पढ़ते ही उनके विस्तार में जाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। नेताजी का स्मृति लोप, किताब का कर्मकाण्ड, तलाश बकरों की, राजनीति के रंगरूटों के लिए प्रशिक्षण योजना, परमलाल की पाप मुक्ति, मानव शरीर के फालतू अंग, दलबदलुओं के लिए सहूलियत और साहित्यकारों के दाँवपेंच आदि। रचनाओं के किरदार भी मज़े के हैं जैसे उम्मीदवार नाहर सिंह और केहर सिंह, जुगाड़ू लाल, कवि नश्तर जी और खंजर जी, छोटेलाल अनमने आदि।

पुस्तक का नाम : ये इश्क़ नहीं आसाँ (व्यंग्य संग्रह)
लेखक : कुन्दन सिंह परिहार
प्रकाशक : वर्जिन साहित्यपीठ
मूल्य : रु 234

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस

रविकान्त राऊत

लेखक स्तंभकार हैं।

युवा भारत: जिसके पास दुनिया है पर अपना रास्ता नहीं

दुनिया उसके मोबाइल में है, पर उसका भविष्य आज भी परिवार की बैठक में तय होता है। यही आज के युवा भारत का पहला बड़ा विरोधाभास है। वह दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय के व्याख्यान को सुन सकता है, किसी विदेशी शहर की सड़क को लाइव देख सकता है, किसी दूसरे महाद्वीप के युवक से मित्रता कर सकता है। उसकी भाषा बदल रही है, उसकी पसंद बदल रही है, प्रेम की उसकी परिभाषा बदल रही है, काम और सफलता की उसकी परिभाषा बदल रही है। लेकिन घर लौटते ही वही पुराना प्रश्न सामने खड़ा होता है - 'आगे क्या करना है?' और इस 'आगे' का अर्थ प्रायः वही होता है जो पिछली पीढ़ी ने तय किया था।

आज की पीढ़ी को शायद सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर होता है कि पिछली पीढ़ियाँ बिना इंटरनेट के कैसे जीवित रह गईं। लेकिन आज के भारतीय युवा की समस्या केवल यह नहीं है कि बेशक उसके पास बहुत अधिक विकल्प हैं। पर विकल्पों की संख्या बढ़ने के साथ उनमें से किसी एक को पा सकने की निश्चितता घटती गई।

एक समय था जब करियर का मतलब था डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, सरकारी अधिकारी या कोई पारंपरिक व्यवसाय। आज एक युवा एक ही सप्ताह में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप, विदेश में पढ़ाई, सरकारी नौकरी, डिजिटल कंटेंट, शेयर बाजार और किसी पहाड़ी कस्बे में कॉफी की दुकान खोलने के सपने देख सकता है।

दुनिया उसके मोबाइल में है, पर उसका भविष्य आज भी परिवार की बैठक में तय होता है। यही आज के युवा भारत का पहला बड़ा विरोधाभास है। वह दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय के व्याख्यान को सुन सकता है, किसी विदेशी शहर की सड़क को लाइव देख सकता है, किसी दूसरे महाद्वीप के युवक से मित्रता कर सकता है। उसकी भाषा बदल रही है, उसकी पसंद बदल रही है, प्रेम की उसकी परिभाषा बदल रही है, काम और सफलता की उसकी परिभाषा बदल रही है। लेकिन घर लौटते ही वही पुराना प्रश्न सामने खड़ा होता है - 'आगे क्या करना है?' और इस 'आगे' का अर्थ प्रायः वही होता है जो पिछली पीढ़ी ने तय किया था।

आज का युवा वैश्विक विचारों से प्रभावित है, लेकिन स्थानीय अपेक्षाओं से बँधा हुआ है। वह स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता पाने में वर्षों लग सकते हैं। वह अपने मन की नौकरी करना चाहता है, लेकिन किराया, ईएमआई, परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी पसंद के साथ बैठकर हिसाब करने लगते हैं। उसके पास स्वप्न हैं, मगर स्वप्न देखने का भी बजट है।

यह पीढ़ी मानसिक रूप से पहले की पीढ़ियों से अधिक खुली हुई है। वह रिश्तों, लैंगिक समानता, मानसिक स्वतंत्रता, निजी पसंद, काम और जीवन के संतुलन जैसे प्रश्नों पर खुलकर बात करती है। लेकिन इसी खुलापन के भीतर एक नई बेचैनी भी पैदा हुई है। सोशल मीडिया ने दूसरों की उपलब्धियों को हमारे घर में स्थायी मेहमान बना दिया है। कोई बीस वर्ष की उम्र में करोड़पति है। कोई पच्चीस में विदेश में है। कोई तीस में अपना स्टार्टअप बेच चुका है। कोई रोज सुबह पाँच बजे उठकर जीवन बदल रहा है।

और हम? हम अभी यह तय कर रहे हैं कि आज रात खाना बाहर खाएँ या घर पर। तुलना ने महत्वाकांक्षा को ईंधन दिया है, लेकिन आत्मसम्मान को कड़वा धुआँ भी दिया है। आज के युवा की एक बड़ी त्रासदी यह है कि उसे असफल होने का अधिकार लगभग नहीं दिया गया।

उससे कहा गया - 'अपने जुनून का पीछा करो।' फिर उसी साँस में तुर्रा यह कि - 'कमाई कितनी होगी?'

उससे कहा गया- 'जो दिल कहे वही करो।' फिर कहा गया- 'लेकिन स्टेबल जॉब है, छोड़ना मत।'

उसे स्वतंत्र बनने के लिए कहा गया और सुरक्षित रहने की सलाह भी दी गई।

वह इसी दोराहे पर खड़ा है।

एक ओर वैश्विक नागरिकता का आकर्षण है, दूसरी ओर मिट्टी से जुड़ने की इच्छा। वह विदेश जाना चाहता है, लेकिन त्योहार पर घर भी लौटना चाहता है। वह निजी स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन परिवार को अकेला छोड़ने का अपराधबोध भी उसे घेरता है। इस पीढ़ी की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद उसकी यह बेचैनी ही है।

आज का युवा पुराने उत्तरों से संतुष्ट नहीं है। वह पूछ रहा है कि सफलता का अर्थ केवल वेतन क्यों हो? नौकरी ही जीवन का उद्देश्य क्यों हो? घर कब लेना है, शादी कब करनी है, बच्चे कब पैदा करने हैं - इन सबके लिए एक सार्वभौमिक समय-सारिणी किसने बनाई? वह पूछ रहा है कि विकास का अर्थ क्या केवल अधिक उपभोग है?

और शायद सबसे कठिन प्रश्न - 'मैं जैसा दिखता हूँ, क्या वास्तव में वैसा ही हूँ?' यह प्रश्न मोबाइल की चमक से कहीं अधिक खतरनाक है। क्योंकि वहाँ से आत्मनिरीक्षण शुरू होता है। भारत का युवा केवल रोजगार की समस्या नहीं है। वह अर्थ की तलाश में भी है। वह ऐसा जीवन चाहता है जिसमें कमाई हो, लेकिन केवल कमाई न हो; स्वतंत्रता हो, लेकिन अकेलापन न हो; सफलता हो, लेकिन अपने आप से दूरी न हो। इसलिए युवा दिवस पर उसे केवल 'देश का भविष्य' कहना पर्याप्त नहीं है। उसे वर्तमान भी मानना होगा।

उसकी बेचैनी को आलस्य न समझना होगा। उसके प्रश्नों को उद्दंडता नहीं कहना होगा। उसकी असहमति को राष्ट्र-विरोध नहीं और उसकी महत्वाकांक्षा को स्वार्थ नहीं मानना होगा। क्योंकि हर नई पीढ़ी पुराने संसार में पैदा होती है, लेकिन उसे उसी संसार में जीना आवश्यक नहीं होता।

भारत का अगला अध्याय शायद वही युवा लिखेगा जो अभी अपने कमरे में बैठकर नौकरी के आवेदन, विदेश की छात्रवृत्ति, प्रेम का संदेश और घर से आया 'कब आ रहे हो?' - चारों एक साथ पढ़ रहा है। उसके पास दुनिया बदलने का सपना है। फिलहाल तो वह अपना पासवर्ड बदलने से शुरू कर रहा है।

छात्रसंघ चुनाव

अमित राव पवार
युवा लेखक हैं।

कॉलेज में लौटती लोकतंत्र की रौनक

करीब नौ वर्षों के लंबे मौन के बाद मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों की आहट फिर सुनाई दे रही है। कैंपस एक बार फिर जीवंत हैं। गलियारों में चुनावी नारों की गूंज है,कक्षाओं में प्रत्याशी विद्यार्थियों से संवाद कर रहे हैं,छात्र अपने भविष्य के प्रतिनिधियों पर चर्चा कर रहे हैं और परिसर का वातावरण लोकतांत्रिक ऊर्जा से भर उठा है। यह दृश्य केवल चुनावी गतिविधियों का नहीं,बल्कि उस लोकतांत्रिक संस्कृति की वापसी का प्रतीक है,जिसकी शुरुआत शिक्षा संस्थानों से होती है।

मेरे लिए यह दृश्य केवल वर्तमान नहीं, बल्कि स्मृतियों का भी हिस्सा है। छात्र जीवन के वे दिन अनायास ही सामने आ खड़े होते हैं,जब मैं स्वयं छात्रसंघ चुनावों में सक्रिय रहा। वर्ष 2000 से लेकर 2017 तक छात्र राजनीति से जुड़ने एवं मार्गदर्शन का एक लंबा अवसर मिला। आज महसूस होता है कि छात्रसंघ चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं,बल्कि नेतृत्व,उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक संस्कारों का पहला विद्यालय हैं।

लोकतंत्र संसद या विधानसभा की सीढ़ियों से नहीं शुरू होता। उसकी पहली सांस विद्यालयों और महाविद्यालयों के परिसर में चलती है। यही युवा मतदान का महत्व समझते हैं,विचारों का सम्मान करना सीखते हैं, असहमति के साथ संवाद करने की कला विकसित करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि नेतृत्व अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। इसी कारण छात्र राजनीति को लोकतंत्र की पहली पाठशाला कहा जाता है। वर्ष 2017 के बाद मध्यप्रदेश के अधिकांश महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए। इस दौरान एक पूरी पीढ़ी कॉलेजों में आई,पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ गई,लेकिन लोकतंत्र का प्रत्यक्ष अभ्यास करने का अवसर उसे नहीं मिला। आज जो विद्यार्थी स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत हैं,उनके लिए यह पहला अवसर होगा जब वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। यह केवल मतपत्र पर मुहर लगाने का अवसर नहीं,बल्कि लोकतांत्रिक नागरिक बनने की दिशा में पहला कदम है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना या रोजगार हासिल करना नहीं होता। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य ऐसे नागरिक तैयार करना है,जो समाज के प्रति संवेदनशील हों,विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हों और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी निभाने का साहस रखते हों। छात्रसंघ चुनाव इन मूल्यों को व्यवहार में सीखने का अवसर देते हैं। यहां विद्यार्थी समझते हैं कि लोकतंत्र केवल बहुमत का नाम नहीं,बल्कि संवाद, सहमति और सम्मानजनक असहमति की संस्कृति का नाम है।भारतीय लोकतंत्र का इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेताओं ने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से ही की संसद,विधानसभाओं और सामाजिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अनेक व्यक्तित्व कभी कॉलेज परिसरों में छात्र प्रतिनिधि रहे। मध्यप्रदेश भी इससे अलग नहीं है। यहां के छात्रसंघों ने ऐसे अनेक नेतृत्व दिए,जिन्होंने आगे चलकर

राजनीति,प्रशासन,शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। इसलिए छात्रसंघ चुनावों को केवल एक वार्षिक औपचारिकता मानना उनके ऐतिहासिक महत्व को कम करके आंकना होगा। समय के साथ छात्र राजनीति का स्वरूप भी बदला है। आज डिजिटल युग में व्हाट्सएप समूह,इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया मंच चुनावी अभियान के प्रमुख माध्यम बन चुके हैं। यह परिवर्तन समय की मांग भी है और अवसर भी।

आज की राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अनेक बार विमर्श की जगह शोर और तथ्यों की जगह भावनात्मक ध्रुवीकरण हावी हो जाता है। यदि यही प्रवृत्ति छात्र राजनीति में भी प्रवेश कर गई,तो लोकतंत्र की पहली पाठशाला अपना मूल उद्देश्य खो देगी। इसलिए यह आवश्यक है कि चुनाव व्यक्तित्वों की लोकप्रियता से अधिक मुद्दों की गंभीरता पर आधारित हों। महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक पुस्तकालय,शोध सुविधाएं,छात्रावास,खेल,महिला सुरक्षा, दिव्यांग-अनुकूल परिसर, डिजिटल संसाधन,स्टार्टअप और कौशल विकास जैसी आवश्यकताओं को चुनावी विमर्श का केंद्र बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को यह समझना होगा कि अच्छे भाषण से अधिक महत्वपूर्ण अच्छी कार्ययोजना होती है।यह भी उतना ही आवश्यक है कि छात्र राजनीति अपनी मूल आत्मा को सुरक्षित रखे। राजनीतिक दलों की वैचारिक प्रेरणा लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा हो सकती है, लेकिन छात्रसंघों की प्राथमिकता छात्रहित ही रहनी चाहिए। यदि चुनाव धनबल, बाहुबल,जातीय ध्रुवीकरण या व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता का माध्यम बनेंगे,तो उनका शैक्षणिक और लोकतांत्रिक उद्देश्य कमजोर पड़ जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन,राज्य सरकार, छात्र संगठनों और स्वयं विद्यार्थियों की यह साझा जिम्मेदारी है कि चुनाव मर्यादित,शांतिपूर्ण और विचार-केंद्रित हों। छात्रसंघ के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए भी यह अवसर केवल विजय प्राप्त करने का नहीं,बल्कि विश्वास अर्जित करने का है। उनका दायित्व प्रशासन और विद्यार्थियों के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करना, समस्याओं के समाधान के लिए रचनात्मक पहल करना और परिसर में सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना है।

मध्यप्रदेश में प्रस्तावित छात्रसंघ चुनाव इसलिए केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं हैं। वे लोकतांत्रिक विश्वास की पुर्नस्थापना का अवसर हैं। नौ वर्षों के बाद लौटती यह चुनावी हलचल केवल पोस्टरों,नारों और मतदान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह विचारों के पुनर्जागरण,संवाद की पुनर्स्थापना और युवाओं की सकारात्मक भागीदारी का उत्सव बननी चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थी चुनाव को अधिकार नहीं,दायित्व के रूप में देखें, उम्मीदवार पद नहीं,सेवा का संकल्प समझें,और विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव को औपचारिकता नहीं, लोकतांत्रिक संस्कृति के उत्सव के रूप में संचालित करे। यदि ऐसा हुआ,तो यह केवल छात्रसंघ चुनावों की वापसी नहीं होगी,बल्कि लोकतंत्र की उस आत्मा का पुनर्जन्म होगा,जो शिक्षा संस्थानों से समाज तक प्रवाहित होती है। क्योंकि इतिहास गवाह है-जब विश्वविद्यालयों में विचार जागते हैं,तब केवल परिसर नहीं जागते,समाज जागता है,राजनीति परिपक्व होती है और राष्ट्र का भविष्य नई दिशा प्राप्त करता है।

जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उत्कृष्ट मॉडल बनेगा 'शिक्षा संजीवनी'

कलेक्टर की पहल पर सीएसआर व जनभागीदारी से शुरू होगा- शिक्षा, अधोसंरचना, डिजिटल लर्निंग, खेल और समग्र विकास पर फोकस

बैतूल। जनजातीय अंचल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने और शासकीय विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने की दिशा में कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे की पहल पर शिक्षा संजीवनी कार्यक्रम तैयार किया गया है। जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा तैयार इस नवाचार को सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) एवं जनभागीदारी के माध्यम से प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। शिक्षा संजीवनी का उद्देश्य केवल विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं में सुधार करना नहीं, बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, डिजिटल शिक्षा, खेल प्रतिभाओं के विकास, करियर मार्गदर्शन और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को एक साथ आगे बढ़ाना है। यह पहल जनजातीय अंचल में शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट और अनुकरणीय मॉडल के रूप में विकसित करने की परिकल्पना पर आधारित है। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता और रुचि की पहचान के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। मेधावी एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क विशेष कोचिंग एवं स्मार्ट क्लासेस उपलब्ध कराने की योजना है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मींस-कम-मेरिट, ओलंपियाड एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए विशेष व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहरों पर निर्भरता कम करते हुए उनके अपने क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

खेल प्रतिभाओं को मिलेगा विश्वस्तरीय प्लेटफॉर्म

शिक्षा संजीवनी में शिक्षा के साथ खेल प्रतिभाओं के विकास को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय खेलों जैसे कबड्डी, खो-खो और एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के साथ आधुनिक खेल मैदान, प्ले-ग्राउंड और उच्च गुणवत्ता वाले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उपलब्ध कराने की योजना है। टैलेंट सर्च के माध्यम से होनहार खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा।

स्कूलों में बेहतर अधोसंरचना और सुरक्षित वातावरण- शिक्षा संजीवनी के अंतर्गत विद्यालयों में आवश्यक अधोसंरचना को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक, स्वच्छ एवं जल-जलयुक्त शौचालय, पर्याप्त बिजली व्यवस्था के लिए सोलर पैनल एवं पर्यावरण अनुकूल व्यवस्थाएं तथा जर्जर भवनों का तत्काल सुधार कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं। विद्यालयों को विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त कक्षों के निर्माण सहित आवश्यक कार्य भी जनसहभागिता और सीएसआर के माध्यम से किए जाएंगे।

डोनेट डेस्क-बेंच से जनभागीदारी को मिलेगा नया आयाम- कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक जनभागीदारी-डोनेट डेस्क-बेंच अभियान है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संस्था विद्यालय के लिए डेस्क-बेंच उपलब्ध कराने में सहयोग कर सकेगी। दानदाताओं के योगदान को विद्यालय के गौरव पटल पर अंकित कर सम्मानित किया जाएगा। इससे समाज के लोगों, उद्योगों, संस्थाओं और पूर्व विद्यार्थियों को विद्यालयों के विकास से सीधे जोड़ते हुए मेरा स्कूल-मेरी जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया जा सकेगा।

पढ़ाई के साथ जीवन मूल्यों व व्यक्तित्व विकास पर ध्यान

कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक मूल्यों पर भी ध्यान दिया गया है। उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार, प्रेरणादायी जीवन आदर्शों से परिचय, पर्यावरण संरक्षण, संवेदनशीलता एवं नैतिक शिक्षा को शिक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा करियर काउंसिलिंग, टूर्नामेंट, खेल प्रतियोगिताएं, विज्ञान प्रदर्शनियां और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे घटकों को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

सीएसआर और जनभागीदारी बनेगी कार्यक्रम की ताकत

कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे की पहल पर तैयार शिक्षा संजीवनी में प्रशासन, शिक्षा विभाग, सीएसआर संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों, समाज और आम नागरिकों की सहभागिता को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी संसाधनों के साथ सामाजिक सहयोग को जोड़कर विद्यालयों में स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण बदलाव लाना है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, विधायक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विधायक भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान, विधायक मुलताई चंद्रशेखर देशमुख, विधायक आमला डॉ योगेश पंडाग्रे, विधायक घोड़ाडोंगरी श्रीमती गंगाबाई उईके द्वारा इस अभिनव प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है।

आरडीपीएस बैतूल की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचम

टेकाथान 2.0 प्रतियोगिता में हासिल किया प्रथम स्थान

बैतूल। उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान आर डी पब्लिक स्कूल बैतूल के विद्यार्थी शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहें हैं। राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंदौर द्वारा नीति आयोग एवं अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से 6 एवं 7 अगस्त को आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय टेकाथान 2.0 प्रतियोगिता में आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल की टीम थंडर ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल कर बैतूल को गौरवान्वित किया है। उल्लेखनीय है कि 6 एवं 7 अगस्त 2026 को इंदौर में

आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देशभर से चयनित 14 श्रेष्ठ टीमों ने भाग लिया था। आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल के कक्षा 10 वीं के छात्र आशुतोष सिंह ठाकुर एवं कक्षा 11 की छात्रा सुहानी वर्मा की टीम थंडर ने अपनी अभिनव सोच, तकनीकी दक्षता, समस्या समाधान क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति के दम पर सभी टीमों को पीछे छोड़ते हुए विजेता का खिताब हासिल किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले तीन चरणों की ऑन लाइन मूल्यांकन प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इन चरणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल की टीम का राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के फाइनल में चयन हुआ। प्रतियोगिता के फाइनल में आरडीपीएस की टीम ने अपने प्रोजेक्ट की उपयोगिता, तकनीकी पक्ष और नवाचार का प्रभावी प्रस्तुतीकरण करते हुए निर्णायकों का ध्यान आकर्षित किया और प्रथम स्थान हासिल किया।

25 हजार पुरस्कार के साथ मिला इनक्यूबेशन सपोर्ट

राष्ट्रीय विजेता बनने पर आरडीपीएस बैतूल की टीम को 25,000 रुपए की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इससे विद्यार्थियों को अपने नवाचार को और विकसित करने तथा उसे भविष्य में उपयोगी तकनीकी समाधान के रूप में आगे ले जाने का अवसर मिलेगा। आरडीपीएस बैतूल की डायरेक्टर श्रीमती ऋतु खंडेलवाल का विजन विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाने के साथ ही उन्हें भविष्य की तकनीकी दुनिया के लिए सक्षम बनाना है।विद्यालय में विज्ञान, तकनीक, नवाचार, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डायरेक्टर श्रीमती खंडेलवाल के मुताबिक आज के दौर में विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ यह भी सीखना जरूरी है कि वे वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझें, उनके समाधान तलाशें और तकनीक के माध्यम से अपने विचारों को मूर्त रूप दें। इसी उद्देश्य से विद्यार्थियों को विभिन्न तकनीकी गतिविधियों, प्रोजेक्ट्स और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उत्कृष्ट सफलता पर दी बधाई

राष्ट्रीय स्तर की टेकाथान 2.0 प्रतियोगिता में उत्कृष्ट सफलता हासिल कर जिले को गौरान्वित करने वाले आरडी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों आशुतोष सिंह ठाकुर एवं सुहानी वर्मा सहित मार्गदर्शक शिक्षकों को आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल की डायरेक्टर श्रीमती ऋतु खंडेलवाल, प्राचार्य, स्टाफ और स्कूल प्रबंधन ने बधाई दी है। विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती खंडेलवाल ने कहा कि विद्यार्थियों की यह सफलता उनकी मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और विद्यालय में विकसित किए जा रहे नवाचार एवं तकनीकी शिक्षा के वातावरण का परिणाम है।

साइबर अपराध से बचने का सबसे बड़ा हथियार जागरूकता और सावधानी : ठाकरे

साइबर हमले हुए तेज और स्मार्ट, विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी से बचने के बताए तरीके

बैतूल। शासकीय महाविद्यालय आठनेर में साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण मंगलवार से शुरू हुआ। प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। सतपुड़ा पर्यावरण समिति अध्यक्ष सतीश ठाकरे ने कहा कि साइबर हमले तेज और स्मार्ट हो गए हैं, ऐसे में बचाव का सबसे बड़ा हथियार जागरूकता है। उन्होंने

बताया कि साइबर अपराधी फर्जी फोन कॉल, मैसेज, ई-मेल और वेबसाइट के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। कई बार ठग बैंक अधिकारी बनकर ओटीपी, एटीएम पिन, पासवर्ड और बैंक खाते की जानकारी मांगते हैं। यह जानकारी साझा करने पर बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। विद्यार्थियों को समझाया कि वे अनजान व्यक्ति के साथ निजी जानकारी साझा न करें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने और अनजान ऐप डाउनलोड करने से बचें। सोशल मीडिया अकाउंट पर मजबूत पासवर्ड के साथ दो-स्तरीय सुरक्षा का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया। प्राचार्य डॉ. सरोज पाटिल ने कहा कि साइबर अपराध से बचने का सबसे अच्छा तरीका जागरूकता और सावधानी है। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं सुरक्षित रहने के साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करे। कार्यक्रम में महाविद्यालय से डॉ. वर्जिनिया दवंडे, प्रो. माधुरी तुम्बेकर, डॉ. साधना ठाकुर, स्पोर्ट ऑफिसर पिनहास दास वाडिया, डॉ. सुरेन्द्र जीतपुरे, डॉ. विकेश कुमार सिंह और प्रो. हरिकिशन कोंगे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. गजानंद ठाकरे ने किया।

दीवा डागा ने देश एवं सतपुड़ा वैली स्कूल बैतूल का नाम विश्व में किया रोशन

कैम्ब्रिज एएस लेवल परीक्षा में 92 प्रतिशत अंक हासिल कर स्कूल कैप्टन दीवा ने रचा कीर्तिमान

बैतूल। सतपुड़ा वैली स्कूल की कक्षा 11वी की छात्रा एवं स्कूल कैप्टन दीवा डागा ने कैम्ब्रिज एएस लेवल एग्जामिनेशन जून 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 92 प्रतिशत का उत्कृष्ट कुल स्कोर हासिल कर विद्यालय और बैतूल का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि ने स्कूल की शैक्षणिक उत्कृष्टता को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। दीवा ने परीक्षा के विभिन्न विषयों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने मैथ्स में 92, इकोनॉमिक्स में 92, साइकोलॉजी में 93 तथा इंग्लिश लिटरेचर में 91 अंक प्राप्त किए। सभी विषयों में उनके शानदार प्रदर्शन ने उनकी मेहनत, लगन और अध्ययन के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। शैक्षणिक उपलब्धि के साथ-साथ दीवा डागा स्कूल कैप्टन के रूप में

अपनी नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारियों का भी प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रही हैं। पढ़ाई, अनुशासन और नेतृत्व के बीच उनका संतुलन विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है। दीवा की इस उपलब्धि से सतपुड़ा वैली स्कूल परिवार में हर्ष का माहौल है। विद्यालय निर्देशिका श्रीमती दीपाली निलय डागा, उप प्राचार्य अरविन्द सिंह राजपूत, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों ने दीवा डागा को उनकी शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित कीं। दीवा डागा की यह सफलता उनकी मेहनत और लगन का परिणाम होने के साथ ही सतपुड़ा वैली स्कूल की शैक्षणिक गुणवत्ता तथा विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर अवसरों के लिए तैयार करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त को निकलेंगी भव्य तिरंगा रैली

बैतूल। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन बैतूल द्वारा 13 अगस्त को भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली प्रातः 10 बजे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम से प्रारंभ होगी। रैली लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम से प्रारंभ होकर शिवाजी चौक, एसपी ऑफिस, कन्या विद्यालय गंज के सामने से होते हुए टांगा चौक, दिलबहार चौक, रेलवे स्टेशन, मैकेनिक चौक, आदिवासी मंगल भवन, कारगिल चौक और अंबेडकर चौक होते हुए शिवाजी ऑडिटोरियम पहुंचेगी, जहां रैली का समापन होगा। तिरंगा रैली में जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, सामाजिक संगठन, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल होंगे। रैली के माध्यम से नागरिकों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को और सशक्त करने का संदेश दिया जाएगा। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने जिलेवासियों से अपील की है कि हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और 13 अगस्त को आयोजित तिरंगा रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों।

नवीन संचालित पैसेंजर ट्रेन समय परिवर्तन की मांग,माखननगर में खुशी का इजहार, नगर संघर्ष समिति का आभार

सोहागपुर। नवीन संचालित होने वाली इटारसी से मदनमहल के लिए प्रस्तावित द यात्री ट्रेन क्रमांक 51673 के संचालन समय परिवर्तन को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया।इस ज्ञापन में नवीन संचालित होने वाली ट्रेन को इटारसी से प्रातः साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे के बीच चलाए जाने एवं गुरमखेड़ी स्टेशन पर स्टापेज करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि नवीन संचालित ट्रेन क्रमांक 51673 इटारसी जंक्शन से प्रातः 11:40 बजे रवाना होकर मदनमहल पहुंचेगी। ज्ञापन में कहा गया है कि सुबह 11:40 बजे इटारसी से ट्रेन चलने के कारण नर्मदापुरम, इटारसी, सोहागपुर एवं आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं सुबह 8 से 9 बजे के बीच ट्रेन चलने से विद्यार्थियों को कॉलेज एवं कोचिंग संस्थानों तक समय पर पहुंचने, नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर पहुंचने तथा व्यापारियों

को दैनिक कार्य निपटाकर समय पर वापस लौटने में सुविधा होगी। इस कारण नवीन संचालित होने वाली ट्रेन के समय में परिवर्तन किया जाए । ताकि यात्रियों को इस ट्रेन का लाभ मिल सके।इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जैसवाल , पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्रसिंह चौधरी ,वरिष्ठ पार्षद धर्मदास बैलबंशी सेवादल अध्यक्ष इरफान खान पार्षद भास्कर मांझी, पूर्व पार्षद मोहन कहार , कांग्रेस के कमलेश मालवीय प्रजापति, प्रतीक तिवारी अनंत तिवारी आदि उपस्थित थे। इधर माखननगर के कांग्रेस नेता एवं पूर्व पार्षद द्वारकाप्रसाद अहिरवार ने फोन पर बताया कि हम इस नवीन संचालित होने वाली ट्रेन के स्टापेज का स्वागत करते हैं। क्योंकि कोरोना के समय सभी ट्रेन इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस ,जनता भागलपुर एक्सप्रेस, बीना एक्सप्रेस, इटारसी इलाहाबाद, सुपरफास्ट पैसेंजर सभी ट्रेनों का स्टॉपेज कोरोना कल के समय में बंद कर दिया गया था केवल नगर वासियों को एक मेमो मेमो ट्रेन ही थी। इन ट्रेनों के स्टार भेज बंद होने के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सभी ट्रेनों के स्टापेज को लेकर माखननगर से बागरा रेलवे स्टेशन तक पदयात्रा वरिष्ठ नेताओं के सानिध्य में की थी। इस नवीन संचालित होने वाली ट्रेन का स्टॉपेज होने का हम स्वागत करते हैं इसके साथ ही रेलवे प्रशासन से आग्रह है कि कोरोना काल में बंद समस्त ट्रेनों का पुनः स्टापेज किया जाए।उधर सोहागपुर नागरिक संघर्ष समति के वकील शिवकुमार पटेल ने कहा कि हमने जो पूर्व में नवीन ट्रेन संचालन के लिए ज्ञापन सौंपे गए थे। प्रशासन ने उक्त बात मानकर नवीन ट्रेन संचालन की घोषणा की है।उसका हम स्वागत करते हैं।

संक्षिप्त समाचार

बोल बम की 22वीं कावड़ यात्रा ओंकारेश्वर रवाना

सुसनेर। सावन मास के पवित्र माह में रविवार को रिमझिम बारिश के बीच 22वीं कावड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। मेला ग्राउंड स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से बोल बम कावड़ यात्रा संघ के तत्वावधान में 50 कावडिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए रवाना हुए। आकर्षक कावड़ कंधों पर उठाए शिवभक्त नगर के प्रमुख मार्गों से निकले।

खिलचीपुर में बाढ़ में फंसे 15 लोगों का रेस्क्यू

राजगढ़। जिले में दिनभर चले राहत बचाव के प्रयासों के बाद शाम को प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। जल मंदिर, सोमवारिया से 6, भोजपुर नाका स्थित बड़े पुल के पास से 3 और बरई माता मंदिर के पास से 6 लोगों समेत कुल 15 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने समन्वय के साथ कार्रवाई की।

कॉलेजों में अतिरिक्त सीएलसी चरण 14 अगस्त तक

राजगढ़। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए 14 अगस्त तक अतिरिक्त सीएलसी चरण आयोजित किया जाएगा। प्रवेश केवल रिक्त सीटों पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। पंजीकृत विद्यार्थी संबंधित कॉलेज में सीधे पहुंचकर दस्तावेज सत्यापन के बाद शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकेंगे। नवीन पंजीकृत विद्यार्थियों को केवल एक कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। 14 अगस्त को शाम 5 बजे तक शुल्क जमा कर प्रवेश लिया जा सकेगा। इसके बाद प्रवेश मान्य नहीं होगा।

सुखड़ नदी उफनी, कई गांवों का संपर्क टूटा

झाड़ला। रविवार रात एक बजे से शुरू हुई तेज बारिश सोमवार दिनभर जारी रही। बारिश से झाड़ला गांव की सुखड़ नदी में बाढ़ आने से पुल पूरी तरह डूब गया और आवागमन बंद हो गया। झाड़ला से बोड़ा, पचोर, बोरखेड़ा, शिंका, इकलेरा और ढाबला सहित कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया, जिससे यात्रियों और किसानों को परेशानी हुई। खेतों से पशुओं के लिए चारा लाने में भी दिक्कत आई। तेज बारिश से कई विद्युत तार टूटने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। कोटरी कलां की नदी में बाढ़ से गांव दो हिस्सों में बंट गया और हाट बाजार में पानी भरने से कारोबार प्रभावित हुआ। कुरावर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह मावई और कोटरी कलां चौकी प्रभारी मेहरबान सिंह मेचन पुलिस बल के साथ दिनभर तैनात रहे।

सावन सोमवार पर बाबा बैजनाथ का किया भव्य श्रृंगार, श्रद्धालुओं का लगा तांता

राजगढ़। श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर दिनभर भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्राचीन खोयरी मंदिर में बाबा बैजनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे। मंदिर में सुबह छह बजे से श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरु हो गया था। दोपहर तक श्रद्धालुओं में गर्भगृह में जाकर बाबा के दर्शन ओर जलाभिषेक किया। इसके बाद दोपहर तीन बजे से भोलेनाथ का श्रृंगार शुरु हुआ। शाम तक चले श्रृंगार दर्शन के बाद शाम 7 बजे महाआरती की गई।

हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा रास्ता, 7 गांवों होते हुए बैजनाथ धाम पहुंची यात्रा

लखनवास। श्रावण मास के पावन अवसर पर ग्राम लोधीपुरा और सीलखेड़ा के ग्रामीणों ने सेकनपुर स्थित पार्वती घाट से पवित्र जल भरकर भगवान भोलेनाथ की भव्य जल यात्रा निकाली। श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए नरसिंहगढ़ स्थित बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। जल यात्रा सेकनपुर से शुरू होकर सीलखेड़ा, लखनवास, लोधीपुरा, पांजरा, पांजरी और हिनौती होते हुए नरसिंहगढ़ पहुंची। यात्रा में महिला, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। श्रद्धालु डीजे की भक्ति धुनों पर नाचते-गाते और हर-हर महादेव व बम-बम भोले के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। पूरे मार्ग में माहौल शिवमय बना रहा। बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने पवित्र जल अर्पित कर सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की।

कार चालक ने बाइक को मारी टक्कर, ईंटों के ढेर से भिड़ी कार

लखनवास। सीलखेड़ा रोड पर शराब के नशे में कार चला रहे चालक ने पहले बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद अनियंत्रित कार सीलखेड़ा जोड़ के सामने सड़क किनारे रखे ईंटों के ढेर से जा भिड़ी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि कार चालक सीलखेड़ा गांव का रहने वाला है और कथित तौर पर शराब के नशे में वाहन चला रहा था। बाइक को टक्कर मारने के बाद कार अनियंत्रित होकर ईंटों के ढेर में जा घुसी, जिससे कार के अगले हिस्से में काफी नुकसान हुआ। हादसे में बाइक सवार और कार चालक के घायल होने की स्थिति की फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है।

11 साल से सावन में पौधारोपण कर रही गो शरण मंडल, 13 अगस्त को लगाएंगे पौधे

ब्यावरा। पर्यावरण संरक्षण और सेवा के उद्देश्य से गो शरण मंडल द्वारा पिछले 11 वर्षों से हर सावन और वर्षा ऋतु में पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। मंडल द्वारा अब तक हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी तय की जाती है, जिससे कई पौधे अब बड़े होकर छाया देने के साथ फल भी दे रहे हैं।

अम्मा बोली थी-कार गुजर गई, हम भी निकल जाएंगे: प्रत्यक्षदर्शी बोले- मना किया था, ड्राइवर नहीं माना; 8 सेकेंड में नाले में समाई कार, 9 मौतें

सारंगपुर। सड़क पर करीब दो फीट पानी था और पास ही नाला था। उसे अंदाजा नहीं था कि वहां सड़क नहीं है। गाड़ी मोड़कर आगे बढ़ा दी। कच्चे में उतरते ही कार 8 सेकेंड में नाले में समा गई।

ये कहना है गणेश गुर्जर का। गणेश ने नाले से चार लाशें निकाली थीं। राजगढ़ के सारंगपुर में सोमवार सुबह मऊ-पड़ाना-तलेन मार्ग पर पड़ाना और झिरी के बीच नाले में ईको कार गिर गई। इसमें तीन बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक देवास जिले की सतवास तहसील के रहने वाले थे। बारिश रुकने के बाद शाम को नाले का पानी उतर गया था। सड़क से आवागमन भी सामान्य हो गया था। घटना के बाद दैनिक भास्कर की टीम ग्राउंड पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों से बात करने पर दो कारण सामने आए। पहला- ड्राइवर की जल्दबाजी और दूसरा- प्रशासन की लापरवाही। जानकारी के मुताबिक हादसे में बचे मुकेश (40) और हुकुम सारंगपुर अस्पताल में भर्ती हैं। मुकेश ने बताया- सुबह करीब 6 बजे सतवास के पास धांसड़ गांव से आ रहे थे। कार में 11 लोग सवार थे। मेरी काकी और हुकुम सिंह की सास सगरबाई को लकवा लगा है। किसी ने सारंगपुर के कनावड़ धाम ले जाने की सलाह दी थी। सोचा था कि एक दिन धाम पर रुकेंगे। दूसरे दिन दिखाकर लौट आएंगे। इसी बीच, अंकल बोले कि आज नहीं पहुंचे तो पर्ची नहीं मिलेगी। कल फिर चक्कर काटना पड़ेगा। उनका बेटा विशाल भी यही बोला। दोनों ने कहा, 'चलो-चलो, निकाल लो।' मैंने बात मानकर गाड़ी पानी में उतार दी।

प्रत्यक्षदर्शी बोला- पलटी खाकर नाले में गिर गई कार : प्रत्यक्षदर्शी महेंद्र परमार ने बताया कि हादसे से ठीक पहले मौके पर मौजूद थे। मैंने कार चालक को पानी में कार नहीं उतारने के लिए कहा था, लेकिन कार में बैठी अम्मा ने कहा कि आगे गाड़ी निकल गई है, हम भी निकल जाएंगे। सड़क पर करीब दो फीट पानी था। इस कारण सड़क दिखाई नहीं दी। वहां बैरिकेड भी नहीं लगा था। आंखों के सामने कार तेज बहाव में नाले में पलटी खाकर चली गई। कुछ ही सेकंड में वाहन और उसमें बैठे ज्यादातर लोग दिखाई देना बंद हो गए।' ड्राइवर और उसके बगल की सीट पर बैठा व्यक्ति बाहर निकल आए।

नाले का न तो साइन बोर्ड और न बैरिकेड लगाए : हादसे वाली जगह पर 65 करोड़ की लागत से करीब 25 किमी लंबी सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग करा रहा है। यहां करीब 12 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा नाला है। सड़क पर करीब 2 फीट पानी और तेज बहाव था। नाले की गहराई या तेज बहाव की चेतावनी देने वाला साइन बोर्ड या रेलिंग नहीं थी। तेज बहाव के दौरान वाहनों को रोकने के लिए अस्थायी बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। एसडीएम रोहित बम्हौरे ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी करीब 15 मिनट में पहुंच गए थे। पुलिया के ऊपर से पानी जा रहा था। पहले से लोगों ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कलेक्टर डॉ. गिरीश मिश्रा ने नाले का गहरीकरण कराने और दोनों पुलियों के बीच क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर पीके शर्मा ने बताया कि नाले के आसपास फिलहाल निर्माण कार्य नहीं चल रहा है।

निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों ने भी कार चालक को रोकने की कोशिश की थी। नाले में मोड़ और अतिक्रमण के कारण बारिश में पानी सड़क पर आया था।

भागवत कथा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर गूंजा नंद के आनंद भयो का जयघोष

संडावता। ग्राम संडावता में चल रही संगीतमय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के चौथे दिन कथा वाचिका एवं राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता कविता जी नागर ने श्रीकृष्ण जन्म की पावन लीला का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने देवकी-वसुदेव के कारावास, कंस के अत्याचार, मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य अवतरण तथा वासुदेव द्वारा बालकृष्ण को यमुना पार कर गोकुल पहुंचाने की लीला का मार्मिक चित्रण किया। श्रीकृष्ण जन्म के अवसर पर आकर्षक झांकी, मंगल गीत, भजन और नृत्य-कीर्तन के साथ पूरा पांडाल भक्तिमय हो उठा। कथा वाचिका के मधुर भजनों पर श्रद्धालु भावविभोर होकर झूमते रहे। इस दौरान पांडाल 'नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की' के जयघोष से गूंज उठा। आसपास के क्षेत्रों से आए अतिथियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा एवं श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। पूरे ग्राम में देर तक उत्सव और भक्ति का माहौल बना रहा।

भावना जैसी होगी, वैसा ही कर्मों का फल मिलेगा : मुनिश्री

सारंगपुर। मनुष्य जीवन में कई तरह के कार्य करता है, लेकिन उन कार्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी भावना होती है। व्यक्ति जिस भावना से कोई कार्य करता है, उसे उसी के अनुरूप फल प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी भावना रखनी चाहिए। मन में किसी के प्रति बुराई, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार नहीं रखना चाहिए। सफलता और वैभव मिलने के बाद भी व्यक्ति को अभिमान से बचना चाहिए। यह बात जैन मुनि प्रवर सागरजी ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए कही।

पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण, जिला प्रभारी मंत्री रहे मौजूद

सुसनेर। नगर परिषद ने रविवार को पुराना बस स्टैंड स्थित पं. दीनदयाल चौक पर पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान रहे। नप अध्यक्ष प्रदीप सोनी ने कहा कि उन्हें काम करने के लिए कम समय मिला है, फिर भी जो काम 40 साल में नहीं हुआ, उसे चार माह में करने का प्रयास किया है। उन्होंने डिवाइडर सड़क की मांग भी रखी। मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण सौभाग्य की बात है। केंद्र और प्रदेश सरकार अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रही है। जिलाध्यक्ष ओम मालवीय ने नप अध्यक्ष की सक्रियता की सराहना की। कार्यक्रम में जयदीप पटेल, पूर्व विधायक बद्रीलाल सोनी, चिंतामण राठौर, रामेश्वर तेजरा सहित भाजपा पदाधिकारी, पार्षद व कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन मुकेश हरदेनिया ने किया।।

खड़े डंपर में घुसी कार, मां-बेटे-बहू की मौत: उज्जैन जा रहा था राजस्थान का परिवार, 2 बच्चे सुरक्षित

सारंगपुर। राजस्थान के धौलपुर से उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए निकला परिवार मंगलवार सुबह सारंगपुर के पास हादसे का शिकार हो गया। आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मऊ के पास अर्टिगा कार सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से जा घुसी। हादसे में कार सवार मां, बेटे और बहू की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे में कार चालक सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें पहले शाजापुर जिला अस्पताल, फिर वहां से इंदौर रेफर कर दिया गया है। कार में सवार दो बच्चे सुरक्षित हैं। सारंगपुर थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी ने बताया कि हादसा मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। मृतकों की पहचान धौलपुर निवासी सोमा (65) पत्नी सुनील त्रिवेदी, अंकुर (42) पिता सुनील त्रिवेदी और अर्चना (40) पत्नी अंकुर त्रिवेदी के रूप में हुई है। घायलों में निहाल (22) पिता अतुल तिवारी और कार चालक अब्दुल हबीद हैं।

निहाल के माथे और अब्दुल के हाथ में चोट लगी है। दोनों को उपचार के लिए शाजापुर जिला अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर दोनों को आगे के उपचार के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया। कार में अंकुर और अर्चना के दो बेटे अंश (14) और तेजस (10) भी थे, जिन्हें कोई चोट नहीं है।

राजगढ़ से कामखेड़ा तक पद यात्रा करेंगे सैकडों श्रद्धालु, लगातार चौथे वर्ष आयोजन

राजगढ़। श्री पातालेश्वर हनुमान मंदिर, बाडिया वार्ड नंबर-1 राजगढ़ में रविवार को मंदिर समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कामखेड़ा बालाजी के दर्शन के लिए सामूहिक पैदल यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। यात्रा में सर्व हिंदू समाज के श्रद्धालु शामिल होंगे। मंदिर समिति के अनुसार पैदल यात्रा 16 अगस्त, रविवार को सुबह 4 बजे श्री पातालेश्वर हनुमान मंदिर से प्रारंभ होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए दो खुपी महादेव मंदिर पर पर भंडारे की व्यवस्था रहेगी। यात्रा की खास बात यह होगी कि श्रद्धालु एक ही दिन में पैदल कामखेड़ा बालाजी मंदिर पहुंचकर सामूहिक रूप से दर्शन करेंगे। कामखेड़ा बालाजी से क्षेत्र की खुशहाली की कामना की जाएगी। कामखेड़ा पद यात्रा का यह निरंतर चौथा वर्ष है। यात्रा में हजारों भक्तों के शामिल होने की संभावना है।

किसानों ने तीन मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, बोले- सप्ताहभर में समाधान नहीं तो आंदोलन

ब्यावरा। भारतीय किसान ने सोमवार को किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम गोविंद कुमार दुबे को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने वर्ष 2025 में खराब हुई सोयाबीन फसल का बीमा भुगतान तत्काल कराने सहित तीन प्रमुख मांगें रखीं। ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले एक महीने से जारी अघोषित बिजली कटौती बंद करने और जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई कराने की मांग भी की गई। किसान संघ पदाधिकारियों ने कहा कि समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं।

बारिश से सारंगपुर क्षेत्र में हाहाकार

सारंगपुर। सोमवार रात करीब से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने सारंगपुर क्षेत्र में हालात बिगड़ गए है। लगातार बारिश से करीब 40 गांव प्रभावित हुए हैं। कई गांवों की बस्तियों और घरों में पानी घुस गया, जबकि नदी-नालों के उफान पर आने से कई मार्गों पर आवागमन बाधित हो गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुट गईं। तेज बारिश की वजह से बिलोदा, पाल, आमागढ़, पढ़ाना, मऊ धनोरा, नारायणपुर, लिमाचोहान, दुग्या, तीतरी, तिसाई और ब्यावरा मांडू सहित कई गांवों में पानी भर गया। कई जगह पानी घरों और बस्तियों तक पहुंच गया। प्रभावित लोगों को प्रशासन की टीमों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। खेतों और सड़कों पर पानी भरने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई।

मेड़तवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर

ब्यावरा। मानव सेवा और सामाजिक सरोकार की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री वैश्य महासम्मेलन युवा इकाई ब्यावरा द्वारा मंगलवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर मेड़तवाल धर्मशाला में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। आयोजकों ने बताया कि रक्तदान किसी जरूरतमंद के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी उद्देश्य से युवाओं और शहरवासियों से अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर रक्तदान करने की अपील की गई है।

उदनखेड़ी और आसपास के ग्रामीण अंचलों में हुई अति भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया

मूसलाधार बारिश... घरों से लेकर उपमंडी तक घुसा पानी

उदनखेड़ी। सोमवार को उदनखेड़ी और आसपास के ग्रामीण अंचलों में हुई अति भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। लगातार मूसलाधार बारिश से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। निचली बस्तियों के कई घरों में घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया। इससे राशन, खाने-पीने की सामग्री, फर्नीचर और घरेलू सामान पानी में डूबने से खराब हो गया। स्थिति यह रही कि कई घरों में दिनभर खाना तक नहीं बन सका, जिससे बच्चों और परिवारों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। तेज बारिश का असर उदनखेड़ी उपमंडी और मुख्य बाजार पर भी पड़ा। उपमंडी परिसर और दुकानों के सामने पानी का तेज बहाव देखने को मिला। जलभराव के कारण दुकानदारों ने दुकानें बंद रखीं और कारोबार पूरी तरह प्रभावित रहा। सड़कों पर पानी भरने से गांव के संपर्क मार्गों पर आवागमन भी बाधित हो गया। खेत तालाब बने, फसलों को नुकसान की आशंका निचले इलाकों और आसपास के खेतों में पानी भरने से वे तालाब जैसे नजर आए। खड़ी फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। उदनखेड़ी के अलावा सुल्तानिया, पीपल्यादेव, रोसिया, सराली, कल्याणपुर, मांग्याखेड़ी, गुवाड़ा, मऊ और पड़ाना में भी बारिश से फसलों और संपत्ति को नुकसान पहुंचने की संभावना है। ग्रामीणों का कहना है कि अचानक जलस्तर बढ़ने और पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था नहीं होने से हालात बिगड़े। उन्होंने प्रशासन से तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू कराने, नुकसान का सर्वे करवाने और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।

लगातार बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त, 527 लोगों का रेस्क्यू

भोपाल में देर झमाझम बारिश, कई मकानों में भरा पानी, शिवपुरी में हाईवे जाम; जबलपुर में युवक डूबा

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में बीते 3 दिन से बारिश का दौर जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को राज्य आपदा प्रबंधन के सिचुएशन रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाढ़ प्रभावित इलाकों को देखा। प्रभावित लोगों का हाल भी जाना। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक प्रदेश में 527 बाढ़ प्रभावितों का रेस्क्यू किया गया है। मंगलवार को देर रात भोपाल में झमाझम बारिश हुई। भोपाल में 2 दिन में 8 इंच पानी गिर चुका है। यहां सोमवार-मंगलवार को सभी स्कूल बंद रहे। करीब 200 मकानों में ढाई फीट तक पानी घुस गया। रास्ते घंटों बंद रहे। कई जगह ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक पानी पहुंचने पर सुरक्षा के लिए सप्लाई बंद करनी पड़ी।

24 घंटे की बात करें तो राजगढ़ के ब्यावरा में 9 इंच, खिलचीपुर में 8 इंच, जीरापुर में 7.7 इंच, राजगढ़ शहर में 4.4 इंच, नरसिंहपुर में 3.7 इंच, पचोर में 3.7 इंच, सारंगपुर में 3.6 इंच बारिश हुई है।

इसी तरह आगर-मालवा के सोयतकलां में 7.7 इंच, आगर शहर में 3.6 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। शाजापुर के गुलाना में 3.8 इंच, गुना के कुंभराज में 3.7 इंच, शाजापुर शहर में 3.4 इंच, मंदसौर के गरोठ में 2.7 इंच, उज्जैन के महिदपुर और माकड़ोन में ढाई इंच पानी गिरा है।

नर्मदापुरम् में लगातार बारिश से नर्मदा नदी का लेवल 9.6 फीट जबकि तवा डैम का जलस्तर 8.5 फीट बढ़ गया है। शिवपुरी में ककरवाया के पास एनएच-46 पर बारिश का पानी भरने से जाम लग गया।

रायसेन में सांची रोड पर पगनेश्वर और भोपाल रोड पर जाखा बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से छोटे पुल डूब गए। जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी रही। सेमरा के पीएमश्री हाईस्कूल परिसर में कमर तक पानी भर गया।

शिवपुरी में न्यू पुलिस लाइन स्टेशन रोड पर पानी से भरे गड्ढे में स्कूली वैन फंस गई। बच्चों ने टायर के नीचे पत्थर डालकर धक्का लगाया। सीहोर में भीलाखेड़ी नदी के पास मकान में एक ही परिवार के 10 लोग घिर गए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उन्हें निकाला।

जबलपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर छीता खुदरी बांध में नहाते समय पश्चिम बंगाल का शेख अब्दुल (35) डूब गया। करीब 48 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद मंगलवार को बांध के दूसरे किनारे पर उसका शव पानी में तैरता मिला। खरगोन में लगातार बारिश के चलते अपरवेदा बांध के दो गेट डेढ़-डेढ़ मीटर खोल दिए गए हैं।

घरों में सांप घुसे, आधी डूब गईं कारें, भोपाल में 1000 से ज्यादा घरों में 2-3 फीट तक पानी भरा

मध्य प्रदेश में इस मानसूनी सीजन के सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम से बाढ़ आ गई। नदियां उफान पर रहीं और कई रास्ते बंद हो गए। राहत के बीच आफत भी खड़ी हुई। भोपाल में 1000 से ज्यादा घरों के आसपास 2-3 फीट तक पानी भर गया। घरों में सांप घुस गए, तो कारें आधी डूब गईं।विदिशा, राजगढ़ और रायसेन समेत कई जिलों में बारिश की वजह से लाखों लोग परेशान हुए। भोपाल बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। शहर के 50 से ज्यादा निचले इलाकों में जलभराव रहा।इनमें सेमरा, शबरी नगर, कैलाश नगर, अशोका गार्डन, वसुंधरा कॉलोनी, जगदीशपुर, पटेल नगर, कंफर्ट ग्रीन कॉलोनी, साईं बाबा रेजीडेंसी, मालीखेड़ी, जानकी अपार्टमेंट और अयोध्या बायपास समेत कई इलाके शामिल हैं।

नदी के बीच से निकाली शवयात्रा, रायसेन में बह गई सड़क, शिवपुरी में हाईवे पर 1 फीट तक पानी

मध्य प्रदेश में 60 घंटे से बारिश का दौर चल रहा है। यह बारिश आफत के साथ राहत भी लाई। नर्मदा, काली सिंध-बेतवा समेत कई नदियां उफान पर हैं। आगर-मालवा और उमरिया में डैम के गेट खुल गए हैं तो भोपाल की लाइफ-लाइन बड़ा तालाब भरने में सिर्फ 4 फीट पानी की जरूरत है। मौसम केंद्र की मानें तो प्रदेश में अब तक 498.3 मिमी, यानी 19.6 इंच बारिश हो चुकी है। हालांकि, यह अब तक की सामान्य बारिश 22.8 इंच (579.7 मिमी) की तुलना में 3.2 इंच कम है। वहीं ओवरऑल 14 प्रतिशत कम पानी गिरा है। इसके बावजूद दो दिन के स्ट्रॉन्ग सिस्टम ने प्रदेश के अधिकांश हिस्से को तर-बतर कर दिया है।

154 करोड़ के ब्रिज से झांकने लगे सरिए, डॉ. अंबेडकर ब्रिज से उखड़ा डामर; कई सड़कें छलनी हो गईं

भोपाल में मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे लंबे ब्रिज डॉ. अंबेडकर (जीजी) फ्लाईओवर की सड़क से सरिए झांकने लगे हैं। रही कसर 2 दिन से हो रही तेज बारिश ने पूरी कर दी। कई जगहों से डामर उखड़ गया है। इधर, बारिश की वजह से शहर की कई सड़कें छलनी हो गई है।यह फ्लाईओवर करीब 154 करोड़ रुपए की लागत से बना है। लोकार्पण के बाद से ही यह सुर्खियों में रहता है। लोकार्पण के ठीक बाद ही सीमेंट क्रांकीट में खुरदुरापन, वाइब्रेशन जैसी समस्याएं सामने आई थीं। कुछ महीने बाद डामर उखड़ गया था।

रीवा लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर और उसके सहयोगी को 50000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा

रीवा (नप्र)। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार के मामलों में कमी नहीं आ रही है। रीवा लोकायुक्त ने अब पीडब्ल्यूडी के प्रभारी चीफ इंजीनियर को 50000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा है। साथ ही एक प्राइवेट व्यक्ति को भी पकड़ा है।

निजी कंपनी के मैनेजर ने की थी शिकायत- दरअसल, पीवीपी एलटीडी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत सोनू सिंह ने लोकायुक्त में शिकायत की थी। यह फर्म निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण करता है। इस कंपनी को लोक निर्माण विभाग, रीवा संभाग में काम दिलाने के एवज में प्रभारी मुख्य अभियंता कैलाश कुमार कच्छे ने हर महीने एक लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी।

लोकायुक्त ने मामले को सत्यापित करवाया- चार अगस्त 2026 को शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने मामले की जांच करवाई। शिकायत में मामला सही पाया गया है। इसके बाद रीवा संभाग के प्रभारी चीफ इंजीनियर कैलाश कुमार कच्छे के लिए ट्रैप दल का गठन किया गया।

पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

छिंदवाड़ा में उड़ान भरने से पहले ही पूर्व सांसद नकुलनाथ के विमान का इंजन फेल

छिंदवाड़ा (नप्र)। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा एयर स्ट्रिप पर मंगलवार सुबह उस समय बड़ा हादसा टल गया, जब पूर्व सांसद नकुलनाथ और कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को लेकर भोपाल के लिए उड़ान भरने वाला विमान अचानक तकनीकी खराबी का

शिकार हो गया। विमान में दोनों नेताओं के साथ स्टाफ के सदस्य भी सवार थे। विमान को उड़ान भरने के लिए तैयार किया जा चुका था और वह रनवे पर खड़ा था। इसी दौरान इंजन में खराबी सामने आई।

विमान को उड़ाने से रोक दिया- स्थिति को भांपते हुए पायलट ने तत्काल विमान को उड़ाने का निर्णय रोक दिया और विमान में सवार सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह पूर्व सांसद नकुलनाथ और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल रवाना होने वाले थे। दोनों नेता छिंदवाड़ा एयर स्ट्रिप पहुंचे। उनके साथ विमान का स्टाफ भी मौजूद था।

इंजन में तकनीकी समस्या आ गई- नेताओं के विमान में सवार होने के बाद उड़ान की तैयारी शुरू हुई। विमान का इंजन चालू किया गया लेकिन कुछ देर बाद विमान में तकनीकी समस्या सामने आ गई।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ की स्थिति का लिया जायज़ा

प्रदेश में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन्स के संबंध में जानकारी प्राप्त की, बचाव कार्यों से 527 लोगों की जान बचाई गई

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य आपदा कमान एवं नियंत्रण केंद्र के सिचुएशन रूम पहुंचकर प्रदेश में अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ की स्थिति का जायज़ा लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जल भराव और बाढ़ की स्थिति से लोगों को बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली तथा प्रभावितों और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे कर्मचारियों और स्थानीय जन से वर्चुअली संवाद किया। सिचुएशन रूम में अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय शुक्ला, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना, निदेशक होमगार्ड श्रीमती प्रज्ञा रिचा उपस्थित थी।

मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, स्थानीय जन की पहल को सराहा- मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड की त्वरित कार्यवाही के

परिणाम स्वरुप 527 लोगों की जान बचाई जा सकी। यह पुलिस- होमगार्ड के कार्य और सेवा भाव का स्वर्णिम पक्ष है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बचाव कार्य में लगे स्थानीय लोगों की पहल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाने वालों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी आवश्यक स्थलों पर दिन-रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। पुलिस-प्रशासन द्वारा सभी जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन को परस्पर समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता होने पर आसपास के जिलों का भी सहयोग लिया जा रहा है। जरूरत होने पर एयर एंबुलेंस की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी।

हरसंभव सावधानी बरतने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जिला अधिकारियों को आपदा की इस स्थिति में पूर्ण सतर्कता, दक्षता, संवेदनशीलता और संयम के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आवश्यक होने पर संभाग और राज्य स्तर से समन्वय कर सहयोग प्राप्त किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अतिवृष्टि जल भराव और बाढ़ की स्थिति में हर संभव सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में पुलिया पर पानी होने पर वाहनों को गुजरने ना दिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिचुएशन रूम से राजगढ़, सीहोर, आगर मालवा, विदिशा, खंडवा चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का वर्चुअल अवलोकन किया।

नए एचटी कनेक्शन से पहले बिजली खर्च का अनुमान जानना हुआ आसान

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने शुरू किया 'अनुमानित मासिक एचटी बिल कैलकुलेटर

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उच्चदाब (एचटी) उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 'अनुमानित मासिक एचटी बिल कैलकुलेटर' की सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट portal.mpcz.in के Consumer Services में HT Service सेक्शन पर उपलब्ध है।

इस ऑनलाइन कैलकुलेटर के माध्यम से नया एचटी कनेक्शन लेने की योजना बना रहे उपभोक्ता प्रस्तावित Contract Demand, संभावित विद्युत खपत, टैरिफ श्रेणी, आपूर्ति वोल्टेज, विद्युत शुल्क तथा TOD खपत जैसी जानकारी दर्ज कर अपने संभावित मासिक बिजली बिल का अनुमान प्राप्त कर सकते हैं।

यह सुविधा उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों एवं अन्य एचटी उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी होगी। इसके माध्यम से उपभोक्ता नया कनेक्शन लेने से पहले संभावित विद्युत व्यय का अनुमान लगाकर अपनी परियोजना की वित्तीय योजना और निवेश संबंधी निर्णय बेहतर तरीके से कर सकेंगे। साथ ही TOD रिबेट/सरचार्ज एवं टैरिफ न्यूनतम (TMM) के संभावित प्रभाव का भी अनुमान लगाया जा सकेगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रस्तावित एचटी उपभोक्ताओं से अपील की है कि नया एचटी कनेक्शन लेने से पहले इस कैलकुलेटर का उपयोग अवश्य करें, ताकि संभावित विद्युत व्यय का अनुमान प्राप्त कर वित्तीय योजना तैयार की जा सके।

भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स में 8 सदस्य मनोनीत, इनमें क्रेडाई अध्यक्ष, कारोबारी-उद्योपगति; एडवाइजर भी बनाए

भोपाल (नप्र)। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) में 8 नए सदस्य मनोनीत किए गए हैं। इनमें बिल्डरों की बड़ी संस्था क्रेडाई अध्यक्ष, कारोबारी और उद्योगपति भी शामिल हैं। वहीं, एडवाइजर भी बनाए गए हैं।

अध्यक्ष गोविंद गोयल ने संस्था की गतिविधियों को और अधिक प्रभावी, व्यापक बनाने, व्यापार-उद्योग जगत के अनुभवी एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सहभागिता किए जाने को लेकर संविधान के नियम 23 (2 व 4) के अंतर्गत विभिन्न सदस्यों एवं वरिष्ठ पदों पर मनोनयन एवं नियुक्तियां की है।

प्रवक्ता अजय देवनानी एवं मंत्री संजीव जैन ने बताया, अध्यक्ष गोयल ने सहयोजित सदस्यों के नामों की घोषणा की। मनोनयन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 8 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सहयोजित सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। इनमें अरविंद

गोयनका, जितेंद्र धाकड़, कन्हैयालाल इसरानी, मनोज सिंह 'मीक', प्रमोद जैन, संजीव गर्ग, वेंकटेश गोयल और विजय गौर शामिल हैं। मीक क्रेडाई के अध्यक्ष भी हैं। वहीं, धाकड़ भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।

इनकी नियुक्तियां भी की- इसके साथ ही चैंबर में वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्तित्वों को संगठन से जोड़ते हुए दीपक लालचंदानी जी को संरक्षक, विनोद जैन और केके बांगड़ को मुख्य सलाहकार बनाया है।

एमपी में रेलवे की महू-खंडवा गेज परिवर्तन परियोजना के लिए काटे जाएंगे 1,40,000 पेड़

भोपाल/इंदौर (नप्र)। मध्यप्रदेश में रेलवे की महू-खंडवा गेज परिवर्तन परियोजना का मार्ग प्रशस्त करने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरने वाले एक मार्गखंड में करीब 1.40 लाख पेड़ काटे जाने को केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अंतिम मंजूरी दे दी है। कटाई मानसून का मौसम बीतने के बाद शुरू होगी। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस अहम परियोजना के तहत रेलवे की ऐतिहासिक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा रहा है।

एक लाख 40000 पेड़ काटे जाएंगे

डीएफओ लाल सुधाकर सिंह ने बताया कि महू-खंडवा रेल लाइन के गेज परिवर्तन की परियोजना के लिए इंदौर और खरगोन जिलों के वन क्षेत्रों में करीब 1.40 लाख पेड़ काटे जाएंगे। डीएफओ के मुताबिक इनमें इंदौर जिले के लगभग 1.24 लाख पेड़ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हमें केंद्र सरकार से पेड़ कटाई की अंतिम अनुमति मिल चुकी है। हालांकि, कटाई का काम मानसून का मौसम बीतने पर अक्टूबर से शुरू होगा।

रेलवे और वन विभाग मिलकर करेगी पेड़ों की कटाई- सिंह ने बताया कि जिस वन क्षेत्र में रेलवे का काम शुरू होगा, उसी क्रम में वहां पेड़ों की कटाई की जाएगी और इसके लिए रेलवे तथा वन विभाग मिलकर योजना तैयार कर रहे हैं। डीएफओ ने बताया कि वन विभाग ने महू-खंडवा रेल परियोजना के लिए रेलवे पर हरित गलियारा प्रबंधन योजना लागू करने की शर्त भी लगाई है।

खाली जमीन पर होगा पौधारोपण- उन्होंने बताया कि इस शर्त के तहत रेलवे को पटरियों के किनारे स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाने होंगे और परियोजना क्षेत्र के भीतर एवं इसके आस-पास उपलब्ध खाली भूमि पर भी पौधरोपण करना होगा। डीएफओ ने बताया कि शर्त के तहत रेलवे को पटरियों के पास वर्षा जल संचयन के ढांचे विकसित करने होंगे और परियोजना के संचालन में ऊर्जा दक्षता के उपाय भी अपनाने होंगे।

रेलवे उठाएगा खर्च- इसके साथ ही डीएफओ ने कहा कि हरित रेलवे गलियारा प्रबंधन योजना लागू होने से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही वन्यजीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। इस योजना का खर्च रेलवे द्वारा उठाया जाएगा और वन विभाग इनकी निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने पेड़ों की कटाई से वन्य जीवन, मिट्टी और नमी पर होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने की योजना अपने स्तर पर बनाई है।

इंदौर में उपलब्ध हैं सीमित जमीन

अधिकारियों के मुताबिक इंदौर जिले में पौधारोपण के लिए सीमित जमीन उपलब्ध है, इसलिए धार और झाबुआ जिलों के वन मंडलों में 916 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे रोपे जाएंगे। हर हेक्टेयर में 1,000 पौधे रोपे जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि महू-खंडवा गेज परिवर्तन परियोजना के तहत 156 किलोमीटर लंबी बड़ी रेल लाइन बिछाई जा रही है, जबकि देश की आजादी से पहले रियासत काल में बिछाई गई छोटी लाइन की लंबाई 118 किलोमीटर थी।

2030 तक पूरा करने का है लक्ष्य

उन्होंने बताया कि गेज परिवर्तन परियोजना का काम 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। महू-खंडवा के बीच नये रेल मार्ग के कारण मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में मशहूर मुंबई के बीच की दूरी कम हो जाएगी तथा पश्चिमी मध्यप्रदेश का दक्षिण भारत से भी संपर्क मजबूत होगा।